राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 235 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरुवार,18 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

कृषि कानूनों के खिलाफ चार घंटे रेल रोको आज, ज्यादातर संगठन असहमत

नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने गुरुवार दोपहर बारह बजे से चार बजे तक रेल रोको अभियान का एलान किया है। हालांकि किसान संगठनों में इसको लेकर मतभेद सामने आए हैं और सांकेतिक रूप से ट्रेन रोकने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद पुलिस-प्रशासन व रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। सिंघु, टीकरी और अन्य उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि स्थानीय लोग ही अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रेन रोकेंगे। सांकेतिक रूप से ही ट्रेनें रोकी जाएंगी। इस दौरान इंजन पर फूलमाला चढ़ाने के साथ चालक को फूल दिया जाएगा और यात्रियों को जलपान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन रोको कार्यक्रम का उद्देश्य बंद ट्रेनों को शुरू करवाना है। यूपी गेट स्थित धरनास्थल से कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। वहीं, एनएचएआइ के नोटिस के संबंध में कहा कि उन्होंने हाईवे की केवल दो लेन घेरी हैं, बाकी खुली हैं। यदि एनएचएआइ ने यादा हरकत की तो वह देश के सभी टोल फ्री करा देंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले वह बंगाल जाएंगे और वहां के किसानों की समस्या सुनकर केंद्र व राय सरकार से जवाब मांगेंगे।

वहीं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (पंजाब) ने पंजाब में 32 जगह ट्रेन रोकने का एलान किया है। सिंघु बार्डर पर कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने मंच से संबोधित करते हुए प्रदर्शनकारियों को कहा, 32 जत्थेबंदियां पंजाब में 32 जगह रेल रोकेंगी। गांवों में भी फोन कर दो कि लोग पत्नी, बच्चों को साथ लेकर यादा से यादा संख्या में रेल रोकने को पहुंचे। जो भी स्टेशन उनके पास पड़ता है, वह वहां जरूर जाएं। पन्नू ने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। 25 फरवरी को तरनतारन में रैली होगी। इसके बाद कपूरथला, जालंधर, मोघा आदि स्थानों पर रैली निकाली जाएगी।

रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के लगभग 20 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में रेल संचालन बंद कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कोशिश रहेगी कि बड़े स्टेशनों पर ट्रेनों को रोका जाए, जिससे यात्रियों को भोजन व अन्य जरूरी सामान आसानी से उपलब्ध हो सके। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उप्र व बंगाल सहित कुछ अन्य इलाकों में आरपीएसएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। खुफिया रिपोर्ट ली जा रही है और उसी के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। आरपीएफ संबंधित रायों की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है।

कोई ट्रेन पूरी तरह से निरस्त नहीं किया गया- रेलवे अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई ट्रेन पूरी तरह से निरस्त नहीं की गई है। जरूरत के अनुसार ट्रेनों को किसी स्टेशन पर रोकने का फैसला किया जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।

सरकार पर दबाव बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन- जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि जिस समय ट्रैफिक सबसे कम होती है, उस समय हमने सड़क जाम किया और इसी प्रकार, दिन में ट्रेन की ट्रैफिक कम होती है क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन यादातर रात में चलती हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरा आंदोलन योजना के मुताबिक हो। रेल रोको आंदोलन का मकसद सरकार पर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है।

रेलवे के संचालन में अगर कोई किसी तरह की बाधा डालता है तो उसके खिलाफ रेलवे ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ट्रेन पर किसी तरह का सामान फेंका जाए या पटरी को नुकसान पहुंचा तो दोषी को रेलवे ऐक्ट की धारा 150 के तहत उम्रकैद दी जा सकती है। धारा 174 कहती है कि अगर ट्रैक पर बैठकर या कुछ रखकर ट्रेन रोकी जाती है तो दो साल की जेल या 2,000 रुपये के जुर्माने या फिर दोनों की सजा हो सकती है। रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने पर, रेल में जबर्दस्ती घुसने पर धारा 146, 147 के तहत छह महीने की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

हजारों किसान पिछले करीब तीन महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। वे केंद्र सरकार की पिछले साल लाए गए तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ आंदोलनकारी नेताओं की 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार ने किसान यूनियनों को नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा उनकी मांगों से संबंधित मसलों का हल तलाशने के लिए एक कमेटी का भी सुझाव था लेकिन आंदोलनकारी किसान संगठन तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं।

पंजाब निकाय चुनावों में कांग्रेस का दबदबा

चंडीगढ़, (एजेंसी)। किसान आंदोलन के बीच हुए पंजाब के नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की एकतरफा जीत हुई है। सात निकायों में से छह पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। वहीं, मोहाली के नतीजे गुरूवार को आएंगे। अभी जिन सात नगर निगमों के नतीजे आए हैं उनकी 350 सीटों में से सबसे ज्यादा कांग्रेस के 268 पार्षद जीते हैं। सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर पर अकाली दल, तीसरे पर आम आदमी पार्टी और चौथे पर भाजपा रही। 2015 में शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड ? वाली भाजपा इस बार चौथे नंबर पर फिसल गई। पिछली बार अकाली दल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तब सभी 5 नगर निगमों पर भाजपा और अकाली दल का ही कब्जा था। इस बार दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, क्योंकि कृषि कानूनों पर तकरार को लेकर दोनों पार्टी अलग हो चुकी हैं। नगर निगम चुनाव में इस बार 2302 वार्डों के लिए 9,222 उम्मीदवार मैदान में थे।

पहली बार 2,832 निर्दलीय चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस के 2,037 और अकाली दल के 1,569 उम्मीदवार थे। भाजपा के 1,003, आप के 1,606 और बसपा के 160 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा।

2015 में पठानकोट नगर निगम पर भाजपा का कब्जा था। इस बार यहां की 50 सीटों में से 37 कांग्रेस के पास गई हैं। भाजपा को सिर्फ 11 सीटें मिली हैं, पिछली बार उसे यहां 30 सीटें मिलीं थीं। अकाली दल को भी इस बार सिर्फ 1 सीट मिली है। हालांकि, उसे पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी।

भारत में पेट्रोल सभी पड़ोसी देशों से महंगा

नई दिल्ली, (संवाददाता)। देश में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100.07 रुपए पर पहुंच गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल इससे आधी कीमत (51.14 रुपए प्रति लीटर) में बिक रहा है। दूसरी तरफ चीन में यह 74.74 रुपए लीटर है। भारतीय रुपए के हिसाब से दुनिया में पेट्रोल की प्रति लीटर औसत कीमत 78.65 रुपए है। भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल 83.19 रुपए लीटर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 89.54 रुपए लीटर है, यानी भारत में दुनिया के औसत भाव से भी पेट्रोल महंगा है। देश में पहली बार किसी शहर में नॉर्मल पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बुधवार से लोगों को एक लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए चुकाने पड़े। ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25-25 पैसे का इजाफा किया। यह लगातार 9वां दिन है, जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं। दिल्ली में पेट्रोल 89.54 रुपए और मुंबई में 96 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है।

इस महीने बीते 14 दिनों में 11वीं बार पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 3.24 रुपए और डीजल 3.47 रुपए महंगा हो गया। इससे पहले जनवरी में रेट 10 बार बढ़े थे। इस दौरान पेट्रोल 2.59 रुपए और डीजल 2.61 रुपए महंगा हुआ था। इस साल अब तक 21 बार में पेट्रोल 5.83 रुपए और डीजल 6.18 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है।

पश्चिम बंगाल चुनाव होगा किसानों का अगला टारगेट: टिकैत

रोहतक । पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में अब राजनीतिक पार्टियों के साथ ही किसान संगठन भी कूदने को तैयार हैं। केंद्र के लाए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का अगला लक्ष्य बंगाल चुनाव है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम पूरे देश का दौरान करेंगे और पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिया कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं देने को कहेंगे जो किसानों की आजीविका छीन रहे हैं। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हार जाते हैं तभी उनका आंदोलन सफल होगा।

किसान नेताओं ने मंगलवार को गढ़ी सांपला में किसान महापंचायत से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कि कई अन्य राज्यों की तरह वे जल्दी ही पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे।

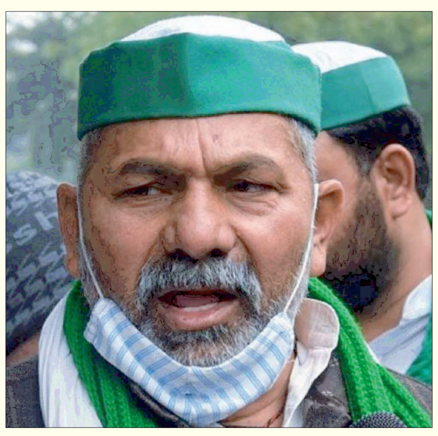

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा, %हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं।

टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, हम देश भर में पंचायतों का आयोजन करेंगे। हम गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य स्थानों पर जाएंगे... हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहां भी एक बड़ी सभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसान राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। हम वहां भी एक पंचायत आयोजित करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रा पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी होगी, टिकैत ने संवाददाताओं से कहा, यह मामला नहीं है, हम किसानों के मुद्दों को लेकर वहां जाएंगे।

हालांकि, हरियाणा बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे पंचायत से संसद तक के चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं दें जो प्रदर्शनकारी किसानों की मदद नहीं करते हैं और उनके आंदोलन को समर्थन नहीं देते।

बाद में टिकैत और कुछ अन्य किसान नेताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए चढ़ूनी ने कहा, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, अगर भाजपा के लोग हार जाते हैं, तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। पश्चिम बंगाल में भी लोग कृषि पर निर्भर हैं। हम वहां जाएंगे और किसानों से आग्रह करेंगे कि वे उन्हें वोट नहीं दें जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं।

टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 40 नेता पूरे देश का दौरा करेंगे ताकि आंदोलन को समर्थन मिले। चढ़ूनी ने कहा कि सरकारें लोगों से ऊपर नहीं हैं और उन्हें आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा, हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाते, भले ही इसका मतलब अंतिम सांस तक लड़ना हो।

पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान नहीं दिया : मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ईंधन की बढती कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेतों में कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। नागापट्टिनम-मदुरै-तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के रामनाथपुरम- थूथूकुडी खंड का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में पीएम ने कहा, क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए? मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि यदि हमने इस विषय पर ध्यान दिया होता तो हमारे मध्यम वर्ग को बोझ नहीं उठाना पड़ता।

उन्होंने कहा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्त्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा-निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि गन्ने से निकाले जाने वाला इथेनॉल आयात को कम करने में मदद करेगा और किसानों को आय का एक विकल्प भी देगा। मोदी ने कहा कि सरकार ऊर्जा के अक्षय स्त्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2030 तक देश में 40 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा, लगभग 6.52 करोड़ टन

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया है। यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। हमारी कंपनियों ने गुणवत्ता वाले तेल और गैस परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में विदेशों में निवेश किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच वर्षों में तेल और गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है और 470 जिलों को कवर करते हुए शहर के गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की दिशा में काम कर रही है।

इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ते हुए प्रधानमंत्री ने मनाली स्थित चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सल्फर रहित (डिसल्फाराइजनेशन) गैसोलीन इकाई भी राष्ट्र को समर्पित की और नागापट्टिनम में कावेरी बेसिन तेलशोधक केन-?द्र की आधारशिला भी रखी।रामनाथपुरम-थूथुकुडी खंड 143 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर करीब 700 करोड़ रुपये की लागत आयी है। इस परियोजना से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) के गैस क्षेत्रों से गैस का उपयोग करने तथा प्राकृतिक गैस को उद्योगों व अन्य व्यापारिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।सल?फर रहित गैसोलीन इकाई के निर्माण पर करीब 500 करोड़ रुपये की लागत आयी है। यह 8 पीपीएम वाली इकाई है और इसे पर्यावरण के अनुकूल गैसोलीन से कम सल्फर का उत्पादन करने वाला बनाया गया है। साथ ही यह उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में योगदान होगा।

बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हो सकती है केंद्रीय बलों की तैनाती

कोलकाता । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे के बाद किसी भी दिन विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है और उसके तुरंत बाद केंद्रीय बलों को सूबे में भेजा जा सकता है। सूत्रों की मानें तो 23 से 25 फरवरी के बीच चुनाव की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को बंगाल आएंगे। वे दक्षिणेश्वर-नोआपाड़ा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन हुगली जिले के डनलप कारखाना मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय बंगाल में एक माह पहले केंद्रीय बल की 28 कंपनियां पहुंची थी और संवेदनशील इलाकों में गश्त लगाई थी जबकि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में 747 कंपनियों की तैनाती की गई थी। इसी तरह बंगाल में 2016 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बल की 40 कंपनियां आई थीं जबकि पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान 720 कंपनियों को तैनात किया गया था।

पिछला विधानसभा चुनाव सात चरणों में हुआ था। इस बार उससे ज्यादा चरणों में चुनाव होने की भी संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बंगाल में मतदान केंद्रों की संख्या 78,603 थी, जो इस बार बढ़कर 1,01,092 हो गई है। मतदान केंद्रों के हिसाब से केंद्रीय बल की कंपनियों को भी बढ़ाया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इसमें 25 से 30 फीसद तक की वृद्धि की जा सकती है। पिछले महीने बंगाल के दौरे पर आई केंद्रीय चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष जाहिर कर चुकी है।

एम.जे. अकबर को झटका, दिल्ली की अदालत ने मानहानि मामले में प्रिया रमानी को किया बरी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम.जे. अकबर की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बड़ी राहत देते हुए पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है।अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद एक फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रिया रमानी ने एम जे अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एमजे अकबर ने प्रिया रामानी के खिलाफ यह कहते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि प्रिया रमानी ने कैंपेन के दौरान किए गए ट्वीट से उनकी मानहानि हुई है। जबकि उनके ऊपर इस तरीके के आरोप इससे पहले कभी नहीं लगे थे। अदालत में इस मामले पर विस्तृत बहस के बाद आज यह फैसला सुनाया गया है। प्रिया रमानी को बरी करते हुए दिल्ली की अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा एक महिला को सालों बाद भी सही अपनी शिकायत रखने का हक है. अदालत ने कहा है कि एक ऐसा शख्स जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी हो, वह यौन उत्पीड़न करने वाला भी हो सकता है। यौन उत्पीड़न से सामाजिक प्रतिष्ठा और मनोबल भी गिरता है। छवि के अधिकार को मयार्दा के अधिकार की कीमत पर नहीं सुरक्षित किया जा सकता। गौरतलब है कि साल 2018 में मी टू अभियान के तहत रमानी ने अकबर पर यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को रमानी के खिलाफ कथित तौर पर उन्हें बदनाम करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी इसी दौरान अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साल 2017 में रमानी ने वोग के लिए एक लेख लिखा जहां उन्होंने नौकरी के साक्षात्कार के दौरान पूर्व बॉस द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने के बारे में बताया। एक साल बाद उन्होंने खुलासा किया कि लेख में उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति एमजे अकबर थे।हालांकि, इससे पहले, अदालत में अकबर ने प्रिया रमानी की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. अकबर ने अदालत को बताया था कि रमानी के आरोप काल्पनिक थे और इससे उनकी प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचा है. दूसरी ओर प्रिया रमानी ने इन दावों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने विश्वास, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक भलाई के लिए ये बातें सबके सामने लाईं।

बाजार में साल के अंत तक आ सकता है कोरोना का टीका, एम्स निदेशक डॉ. गुलेरिया ने जताई उम्मीद

नई दिल्ली । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को बताया कि कोरोना का टीका इस साल के अंत तक बाजार में आ सकता है। गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन खुले बाजार में तभी उपलब्ध होगा जब प्राइम टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा और आपूर्ति व मांग में समानता होगी। उम्मीद है कि 2021 के अंत या उससे पहले वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। बुधवार को कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने के बाद डॉ. गुलेरिया ने कहा कि मैं सब से कहना चाहता हूं कि वैक्सीन से न घबराए और टीका लगवाएं। कोरोना संक्रमण से हालात अब लगभग सामान्य हो चुके हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन इसे हमें ठीक बनाए रखना होगा। उसके लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। डॉ. रणदीप गुलेरिया ने 16 जनवरी 2021 को एम्स में वैक्सीन का पहला डोज लिया था। दूसरा डोज 28 दिन के बाद लेना होता है। बुधवार को वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद उन्होंने ये बातें कहीं। इससे पहले मंगलवार को नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने भी एम्स में स्वदेशी कोवैक्सीन टीके की दूसरी डोज ली। उन्होंने 16 जनवरी को टीके की पहली डोज ली थी। डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश के लोग स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा रखें। वैक्सीन लगवाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें। भारत में बनी वैक्सीन उपयोगी है। 16 से 19 जनवरी तक कुल 12,853 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली डोज दी गई थी, जो दूसरी डोज टीका के लिए योग्य हैं। 'इनमें से अब तक 51.18 फीसद कर्मचारियों ने ही टीके की दूसरी डोज ली है।

ऑस्ट्रेलिया शर्मसार: पूर्व महिला कर्मचारी का आरोप- 2 साल पहले संसद में रक्षा मंत्री के चैम्बर में सहयोगी ने रेप किया, पीएम ने मदद नहीं की

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी ने संसद भवन में रेप का आरोप लगाया है। 26 साल की ब्रिटनी हिगिन्स का आरोप है कि 2018 में वो एक रात पार्टी में गई थी। वहां उसने शराब पी। एक सहयोगी उसे पार्लियामेंट हाउस में डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस लेकर आया। उसके साथ रेप किया गया। उस वक्त स्कॉट मॉरिसन की गठबंधन सरकार थी। प्रधानमंत्री ने इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कराई। महिला ने रेपिस्ट का नाम फिलहाल नहीं बताया है।

ब्रिटनी का आरोप

हिगिन्स तब 24 साल की थीं। उनके मुताबिक- मैं अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक पार्टी में गई थी। वहां शराब पी। मेरे एक साथी ने मुझे घर छोड़ने का ऑफर दिया। लेकिन, वो व्यक्ति मुझे मेरे घर छोड़ने के बजाए पार्लियामेंट हाउस ले गया। यहां उसने डिफेंस मिनिस्टर के चैम्बर में मेरे साथ रेप किया। मुझे कुछ होश आया। उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही।

ब्रिटनी आगे कहती हैं- मैंने अपने साथ हुई बदसलूकी की जानकारी अपने साथियों को दी। सरकार और पुलिस को भी इस बारे में विस्तार से बताया और सबूत दिए। डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुझे इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।

रेपिस्ट का नाम नहीं बताया

ब्रिटनी ने अब तक उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, जिसने उनके साथ रेप किया। हालांकि, ये जरूर कहा कि वो व्यक्ति लिबरल पार्टी का उभरता हुआ पॉलिटिशियन है। ब्रिटनी ने ये माना है कि उस रात वे काफी नशे में थीं। उन्होंने कहा- मैंने डिफेंस मिनिस्टर को इस बारे में जानकारी दी थी। 12 अन्य लोगों को भी इस बारे में बताया। इस घटना के कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री मॉरिसन ने देश में चुनावों का ऐलान कर दिया था।

अब मॉरिसन घटना पर दुख जताते हुए मान रहे हैं कि जांच सही तरीके से नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि पार्टी ने हिगिन्स पर पुलिस कम्प्लेंट वापस लेने का दबाव बनाया। हिगिन्स का आरोप है- मुझसे कहा गया कि अगर नौकरी बचानी है तो पुलिस केस वापस लीजिए। मैंने नाइंसाफी की शिकार हुई और मुझे ही चुप रहने को कहा गया।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 15 साल से ऊपर की हर छह में से एक लड़की सेक्शुअल वॉयलेंस यानी यौन हिंसा का शिकार होती है। कई मामलों में वे वर्क प्लेस पर इसका शिकार बनती हैं।

दुनिया की सबसे पुरानी बीयर फैक्ट्री-मिस्र में 5000 साल पुराने 8 स्ट्रक्चर मिले, मिट्टी की 40 टंकियों में एक साथ 22 हजार लीटर शराब बनती थी

अबाइडौस। मिस्र के सबसे पुराने शहर अबाइडौस में दुनिया की सबसे पुरानी बीयर फैक्ट्री मिली है। अमेरिका और इजिप्ट के ऑर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि यह फैक्ट्री 5000 साल पुरानी है। यहां मिट्टी के बेसिन (टंकियों) में एक बार में करीब 22 हजार लीटर बीयर बनाई जाती थी। तब नार्मर राजवंश यहां के शासक थे। ऑर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई में बीयर बनाने की 8 यूनिट्स मिली हैं। हर यूनिट की लंबाई करीब 65 फीट और चौड़ाई करीब 8 फीट के आसपास है। एक यूनिट में बीयर बनाने के लिए मिट्टी के 40 बेसिन का इस्तेमाल किया जाता था।

ऑर्कियोलॉजिस्ट ने अबाइडौस शहर में खुदाई की थी। इस शहर को प्राचीन मंदिरों और पुरातत्व खोजों के लिए जाना जाता है। यह शहर नील नदी के दक्षिणी हिस्से में रेगिस्तान में मौजूद है। जो कायरो शहर से करीब 450 किलोमीटर दूर है। एक वक्त यह शहर पर्यटकों से गुलजार रहता था। साल 2011 के बाद राजनीतिक उथल-पुथल के कारण इस शहर में हालात काफी खराब हो गए। खोज के को-डायरेक्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉ. मैथ्यू एडम्स के मुताबिक, प्राचीन मिस्र में राजशाही ठाठ के लिए इस बीयर फैक्ट्री को बनाया गया होगा। फैक्ट्री का निर्माण शायद उस इलाके में किया गया, जहां बलि दी जाती थी। उस वक्त हो सकता है शराब पी जाती हो। इससे पहले ब्रिटिश ऑर्कियोलॉजिस्ट ने 1900 ईस्वी में इस बीयर फैक्ट्री का जिक्र अपनी किताब में किया था। हालांकि वह इसकी सटीक लोकेशन नहीं बता पाए थे।

एयर एंबुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग: फ्यूल कम होने की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा भारतीय विमान

इस्लामाबाद। भारतीय एयर एंबुलेंस की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसकी वजह रीफ्यूलिंग बताई जा रही है। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि एयर एंबुलेंस ने रविवार को पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी से संपर्क किया। बताया कि विमान में फ्यूल कम पड़ गया था।

ब्रिटिश मरीज को लेकर जा रहा था

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एयर एंबुलेंस में ब्रिटिश मरीज था। उसके साथ एक डॉक्टर और दो नर्स भी थीं। वे सभी कोलकाता से ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे जा रहे थे। सीएए की इजाजत मिलने के बाद एयर एंबुलेंस ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। करीब दो घंटे बाद रिफ्यूलिंग कर विमान ने उड़ान भरी। इससे पहले 17 नवंबर 2020 को भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से एक विमान की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। विमान रियाद से दिल्ली आ रहा था। इसमें सवार बरेली के एक युवक को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिससे उसकी जान चली गई थी।

पहला अल्ट्रा-रियलिस्टिक रोबोट-आई-दा है दुनिया की पहली रोबोट पेंटर, आइना देखकर बना लेती है अपनी तस्वीर

लंदन। आई-दा खूबसूरत दिखने वाली महिला असल में एक रोबोट है । सिर्फ रोबोट ही नहीं, ये एक बेहतरीन पेंटर भी है। हाल ही में इन्होंने एक कमाल किया है। आइने में खुद को देखकर अपनी पेंटिंग बना डाली। इसके बाद से ये लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इसे बनाने वाले लोगों ने इसका नाम 19वीं सदी की गणितज्ञ अदा लवलेस के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया का पहला अल्ट्रा-रियलिस्टिक रोबोट है जो अपनी आंखों और हाथों के उपयोग से पेंटिंग बनाती है । आई-दा ने अपनी पेंटिंग बनाने के लिए हाल ही में खुद को आइने में देखा। सारे कॉर्डिनेट्स रिकॉर्ड किए। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालिसिस किया, उसके बाद उसने अपनी तस्वीर को कैनवास पर उतार दिया । मेलर ने बताया कि आई-दा दुनिया का पहला प्रोफेशनल ह्यूमेनॉयड आर्टिस्ट है, जो अपनी कलाकृतियां खुद बनाता है।

फॉरेन डिप्लोमैट्स का कश्मीर दौरा: बौखलाए पाकिस्तान ने कहा- दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है भारत

इस्लामाबाद। विदेशी राजनयिकों का एक दल जम्मू-कश्मीर के मैदानी हालात का जायजा लेने के लिए यहां पहुंच रहा है। इसमें यूरोपीय यूनियन के डिप्लोमैट्स भी शामिल होंगे। ये स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। भारत की इस कवायद से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश विभाग का आरोप है कि विदेशी राजनयिकों को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर ले जाकर भारत दुनिया को गुमराह करना चाहता है।

भारत ने साजिश रची

पाकिस्तान के विदेश विभाग द्वारा सोमवार रात जारी बयान में फॉरेन डिप्लोमैट्स के कश्मीर दौरे को प्रायोजित बताया गया है। विदेश विभाग ने कहा- यह पूरी तरह से प्रायोजित दौरा है। हम इसकी निंदा करते हैं। भारत दुनिया को इस कोशिश के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।

जमीनी हकीकत अलग

पाकिस्तान के विदेश विभाग द्वारा जारी बयान को गौर से देखें तो साफ नजर आता है कि वो फॉरेन डिप्लोमैट्स के दौरे से खुश नहीं है। इसमें कहा गया- कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हैं। वहां 18 महीने से फौज का शासन का है। कश्मीर को बाकी दुनिया से अलग कर दिया गया है। लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। हम दुनिया के देशों से अपील करते हैं कि वो भारत को कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए कहे ताकि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके।

पिछले महीने भी विदेशी राजनयिक कश्मीर गए थे: पिछले महीने ही अमेरिकी राजदूत के नेतृत्व में 15 सदस्यीय डेलिगेशन ने कश्मीर का दौरा किया था। इस बार डेलिगेशन में यूरोपियन यूनियन और खाड़ी देशों के राजनयिक शामिल रहेंगे।

पिछले दौरे में यूरोपियन प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर दौरे पर जाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि वह 'गाइडेड टूर' के पक्ष में नहीं हैं और बाद में वहां जाएंगे। इसके चलते पिछले दौरे में में अमेरिकी राजदूत कैनेथ जस्टर समेत बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, नाइजीरिया और अन्य देशों के राजनयिक कश्मीर गए थे। ईयू के राजनयिकों ने कहा था कि वे अपनी मर्जी से चुने गए नेताओं से मिलना चाहते थे।

कोरोना दुनिया में: दूसरे देशों को वैक्सीन दे सकती है ब्रिटेन सरकार, इजराइल में अफवाहों से वैक्सीनेशन पर असर

वॉशिंगटन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.96 करोड़ से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 18 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

दूसरे देशों को वैक्सीन देगा ब्रिटेन

अमीर देशों की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वे वैक्सीन का जरूरत से ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं और इसकी वजह से गरीब या जरूरतमंद देशों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ब्रिटेन सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ओवर स्टॉक वैक्सीन दूसरे और जरूरतमंद देशों को दिया जाए, ताकि वहां संक्रमण और मौतें रोकी जा सकें। इस बारे में वहां के वैक्सीन डिप्लॉयमेंट मिनिस्टर नदीम जाह्वी ने कहा- हम चाहते हैं कि ब्रिटेन के वयस्कों को सबसे पहले वैक्सीन मिले। इसके बाद जो भी हमारे पास ज्यादा स्टॉक होगा वह दूसरे देशों को दिया जाए। इस बारे में प्लान तैयार किया जा रहा है।

इजराइल में नई दिक्कत

इजराइल में ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेट करने की तैयारी है, इसमें काफी सफलता भी मिली है और देश में संक्रमण काफी हद तक रोका जा सका है। लेकिन, सरकार के सामने दूसरी दिक्कत यह है कि यहां पर वैक्सीन को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसकी वजह से प्रॉसेस पर असर पड़ा। सरकार ने वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाहें फैला रहे लोगों को चेतावनी भी दी है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा- अगर आपको जिम या कल्चरल इवेंट्स में जाना है तो वैक्सीनेशन कराना ही होगा। सरकार ने इस परेशानी से निपटने के लिए डिजिटल टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है।

अमेरिकी फौज पर हमला: इराक के इरबिल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, 1 की मौत कई घायल

इरबिल। इराक के इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार रात रॉकेट हमला हुआ। इसमें एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। इस एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर अमेरिकी फौज का एयरबेस है और माना जा रहा है कि हमले में अमेरिकी फौज को ही निशाना बनाने की साजिश थी। अमेरिका ने घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रहा है। हमले के पीछे ISIS का हाथ माना जा रहा है। यह आतंकी संगठन इराक में फिर ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है।

एयरबेस ही था निशाने पर

हमले को अमेरिका ने गंभीरता से लिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन खुद मीडिया के सामने आए। कहा- हम इस हमले को गंभीरता से ले रहे हैं। जांच चल रही है। जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रॉकेट हमले के निशाने पर अमेरिकी सैनिक और एयरबेस ही था।

एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत

ब्लिंकेन ने कहा- फिलहाल, हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक, एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर हमले में मारा गया है और कई लोग गंभार रूप से घायल है। घायलों में एक अमेरिकी भी शामिल है। मैं इस बारे में कुर्दिश प्रांत के प्राइम मिनिस्टर के संपर्क में हूं। मैंने उनसे साफ कहा है कि वे साजिश को अंजाम देने वाले लोगों या संगठन का पता लगाएं। किसी भी सूरत में अमेरिकी हितों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

तीन रॉकेट दागे गए

इराकी और नाटो फौज के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी से कहा- तीन रॉकेट दागे गए। एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इस जगह विदेशी सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा हैं। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

फिलहाल, सुरक्षा के मद्देनजर इरबिल के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। माना जा रहा है कि आज दोपहर तक अमेरिका अपना एक जांच दल यहां भेज सकता है। पिछले साल 20 दिसंबर को भी इस एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी।

फौज को मैसेज

इमरान को पीएम बनाने जैसा धोखा मुल्क के साथ दोबारा मत करना, लोग जीना मुश्किल कर देंगे : मरियम

इरबिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने एक बार फिर फौज को निशाने पर लिया। सोमवार को वजीराबाद की रैली में उन्होंने सीधे तौर पर फौज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहले की तरह इमरान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और फौज को सिलेक्टर्स बता दिया। मरियम ने कहा- सिलेक्टर्स को मेरा साफ मैसेज है कि अगली बार इमरान को सिलेक्ट करने की गलती न करे, नहीं तो अवाम जीना मुश्किल कर देगी।

लोग मुश्किल में और इमरान मौज कर रहे

विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इस रैली में एक लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। भीड़ इतनी थी कि मरियम को स्टेज तक पहुंचने में ही एक घंटा लगा। रैली को संबोधित करते हुए मरियम ने कहा- लोग भूख से मर रहे हैं, हर चीज महंगी हो गई है। मैं इमरान के सिलेक्टर्स से कहना चाहती हूं कि वे उन्हें फिर चुनने की गलती बिल्कुल न करें, नहीं तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, आपका जीना मुश्किल कर देंगे।

मैं पाकिस्तान की बेटी

मरियम ने आरोप लगाया कि इमरान सरकार पंजाब प्रांत को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा- मैं पाकिस्तान और पंजाब की बेटी हूं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसे बांटने की साजिश नाकाम कर दी जाएगी। ये सोचना होगा कि सरकार पंजाब के लोगों की रोटी और आटा छीनने की कोशिश क्यों कर रही है। इसलिए मैं फिर कह रही हूं कि इमरान को सिलेक्ट करने वाले लोगों को सोचना होगा कि ये गलती दोहराई न जाए। लोग आज जब इन सिलेक्टर्स के बारे में बुरा बोलते हैं तो दुख होता है, आखिर ये हमारे देश का ही हिस्सा है।

अपना काम करें सिलेक्टर्स: मरियम ने कहा- मैं सिलेक्टर्स को मैसेज देना चाहती हूं कि उनका जो काम है, वो वही करें। सियासत में उनकी दखलंदाजी अच्छी नहीं लगती। लोगों के काम में आप क्यों दखल दे रहे हैं। ये मुल्क टूट रहा है और इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। नवाज शरीफ फिर वापस आएंगे और देश के मामले हम सुधारेंगे। इस सरकार और उसे चलाने वालों ने देश को सिर से पैर तक कर्जों से लाद दिया है। इसका जवाब कौन देगा। देश में फिर हमारी सरकार आने वाली है।

न्यूजीलैंड के एक शहर में लॉकडाउन तो दूसरे में जश्न

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड लॉकडाउन की जद में आ गया, जबकि दूसरा शहर वेलिंगटन जश्न में डूबा दिखाई दिया। दरअसल, राजधानी वेलिंगटन में 34,500 क्षमता वाले स्काई स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। इसमें मशहूर बैंड सिक्स-60 ने प्रस्तुति दी। इसे नाम दिया गया- 'धरती का सबसे बड़ा शो।' जिसमें करीब 32 हजार लोग शामिल हुए।

वेलिंगटन की आबादी करीब 2.16 लाख है और न्यूजीलैंड का तीसरा बड़ा शहर है। यानी कॉन्सर्ट में शहर की 15 फीसदी आबादी मौजूद रही। वो भी तब, जब 16.7 लाख की आबादी वाले सबसे बड़े शहर में तीन दिन का लॉकडाउन लग चुका है।

ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल बबल पर बैन लगाया

ऑकलैंड में लॉकडाउन लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 72 घंटों के लिए ट्रैवल बबल पर बैन लगा दिया है। न्यूजीलैंड से पहुंचने वाले सभी विमानों को रेड जोन में रखा गया। वहीं, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया जा रहा है।

अमेरिका में कोरोना के सात नए रूप मिले, ये ब्रिटेन और अफ्रीकी वैरिएंट जैसे ही हैं

अमेरिका में कोरोना वायरस के सात नए वेरिएंट मिले हैं। ये नए वैरिएंट ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रिका में मिले कोरोना के नए स्वरूप से मिलते-जुलते रूप में ही विकसित हो रहे हैं।

एक अध्ययन के आधार पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने यह जानकारी दी है। हालांकि रिसर्चर अभी इस बात पर एकमत नहीं है कि ये नए वैरिएंट ब्रिटेन वाले की तरह ही संक्रामक हो सकते हैं। लेकिन स्टडी में इसकी पूरी आशंका जताई गई है कि नए वैरिएंट ज्यादा संक्रामक हो सकते हैं।

लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के वॉयरोलॉजिस्ट और स्टडी के सह-लेखक जेरेमी कामिल ने कहा कि, यह स्पष्ट है कि इस म्यूटेशन के साथ कुछ चल रहा है। लेकिन वैज्ञानिक इस पर शंकालु हैं कि नया म्यूटेशन ह्यूमन सेल में कैसे प्रवेश कर रहा है।

कागज, कपड़े पर वायरस कम दिन जिंदा रहता है

आईआईटी मुंबई के रिसर्चरों ने एक अध्ययन के आधार पर कहा है कि कांच और प्लास्टिक वाली सतहों की तुलना में कागज और कपड़े पर कोरोना वायरस कम दिनों तक जीवित रह सकता है। 'फिजिक्स ऑफ फ्लूड्स' नामक पत्रिका में यह रिसर्च प्रकाशित हुई है।

2021 इंडियास्पोरा गर्वनमेंट लीडर्स: अमेरिका, ब्रिटेन समेत 15 देशों में 200 से अधिक भारतीय लीडरशिप की भूमिका में

वाशिंगटन। दुनियाभर में भारत और भारतीय लोगों का डंका बज रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 15 देशों में 200 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग लीडरशिप वाले पदों पर काबिज हैं। 60 लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी देश के मंत्रिमंडल में हैं। '2021 इंडियास्पोरा गर्वनमेंट लीडर्स' की पहली रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। इंडियास्पोरा के मुताबिक, अभी कई अन्य देशों में स्टडी जारी है। इसके बाद दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी जहां, भारतीय मूल के लोग टॉप अथॉरिटी और लीडरशिप की भूमिका में हैं। 'इंडियास्पोरा' के फांडर और बड़े इंडस्ट्रलिस्ट में शुमार एमआर रंगास्वामी ने कहा, 'यह हर भारतीय के लिए गर्व करने की बात है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल की हैं।' अमेरिका की सांसद अमी बेरा ने कहा, '2021 इंडियास्पोरा गर्वनमेंट लीडर्स' की सूची में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। संसद में सबसे लंबे समय से सेवाएं दे रहे सांसद के तौर पर, मुझे भारतीय-अमेरिकी समुदाय का नेता बनकर गर्व है। यह समुदाय अमेरिकी जीवन एवं समाज का अभिन्न अंग बन गया है।'

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, यूएई, ब्रिटेन, अमेरिका में भी डिप्लोमैट्स, बिजनेसमैन, बैंकिंग, राजनीति समेत कई क्षेत्रों में भारतीय मूल के लोग बड़े पदों पर काबिज हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक, 3.2 करोड़ से ज्यादा भारतीय दुनिया के कई देशों में हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं।

जहां, भारतीय लोग वहां की GDP 28 ट्रिलियन

'इंडियास्पोरा' के मुताबिक, '2021 इंडियास्पोरा गर्वनमेंट लीडर्स' की लिस्ट में शामिल भारतीय मूल के लोग जिन देशों में टॉप पोजिशन पर हैं, वहां की GDP करीब 28 ट्रिलियन डॉलर की है। इससे भारतीय लोगों के दबदबा का पता चलता है। इंडियास्पोरा एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में भारतीय मूल के लोगों के लिए काम करती है। इसके फाउंडर एमआर रंगास्वामी हैं। रंगास्वामी अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों में भी शुमार हैं।

26 जनवरी को लाल किला पर तलवारबाजी करने वाला महिंदर उर्फ मोनी गिरफ्तार

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लाल किला हिंसा में मुख्य आरोपित महिंदर सिंह उर्फ मोनू को भी धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस अब तक लाल किला हिंसा मामले में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू, इकबाल सिंह समेत आधा दर्जन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के पीतम पुरा इलाके से महिंदर को गिरफ्तार किया है।

महिंदर पेशे से मैकेनिक है और एसी रिपेयर का काम करता है। वह अपने परिवार के साथ दिल्ली के स्वरूप नगर में रहता है। यहां पर बता दें कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। इस में 100 से अधिक पुलिसवाले भी घायल हुए थे। लाल किला पर हिंसक किसान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान जुगराज सिंह नामक शख्स ने लाल किला पर लगे तिरंगे के बगल में अन्य झंडा भी फहरा दिया था।

वहीं, लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में आरोपित दीप सिद्धू की पुलिस हिरासत तीस हजारी अदालत ने सात दिन के लिए बढ़ा दी है। पुलिस ने मंगलवार को सिद्धू को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भुजाली के सामने पेश किया गया। पुलिस ने इस दौरान अन्य आरोपितों की पहचान करने और मामले की जांच के संबंध में आगे की पूछताछ के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग की। पुलिस की अपील पर अदालत ने पुलिस हिरासत को सात दिन के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले पुलिस ने सिद्धू को नौ फरवरी को सात दिन की हिरासत में लिया था। पुलिस ने अदालत को दलील दी कि लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में सिद्धू मुख्य आरोपित है। उसने मौके पर मौजूद रहकर तमाम इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये लोगों को उकसाया था। लिहाजा, उसके जरिये अन्य आरोपितों की पहचान की जानी है। वहीं, सिद्धू के अधिवक्ता ने दावा किया कि उनके मुवक्किल का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है और वह गलत समय पर गलत जगह पर था।

सिंघु बॉर्डर पर एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों पर तलवार से हमला, पुलिस की जीप लेकर भागा आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले निहंग प्रदर्शनकारी को कुछ घंटे की मशक्कत के बाद दबोच लिया गया। मंगलवार शाम को आरोपित निहंग हरप्रीत ने पहले तो सिंघु बॉर्डर पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला किया फिर वह पुलिस की जीप लेकर ही भाग गया। इसके पुलिस की जीप छोड़ी तो स्कूटी लेकर भागने लगा।

इस बीच पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, इस दौरान पकड़े जाने से पहले हरप्रीत ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर भी हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपित हरप्रीत ने पहले सिंघू बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों पर तलवार से हमला किया और एक फिर पुलिसकर्मी की कार भी छीन ली। इसके बाद सूचना पर मिलने पर समयपुर बादली के थानाध्यक्ष आशीष दुबे ने मुकरबा चौक तक उसका पीछा किया (सिंघु से लगभग 10 किलोमीटर) तो उसने उनपर भी हमला कर दिया।

बाद में पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। निहंग की पहचान पंजाब के हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पूरा हादसा मंगलवार रात को हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपित हरप्रीत के खिलाफ हत्या और चोरी के प्रयास का मामला भी दर्ज है। उससे और पूछताछ जारी है। घटनाक्रम के मुताबिक, मंगलवार रात को करीब 8 बजे हरप्रीत सिंह नाम के प्रदर्शनकारी ने तलवार के बल पर पहले दिल्ली पुलिस के एक जवान की कार छीन ली। फिर इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो वो मुकरबा चौक पर कार छोड़कर एक स्कूटी लेकर फिर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान पुलिस बल जिसमें एसएचओ समयपुर बादली आशीष दुबे अपने बाकी स्टाफ के साथ जब उसका पीछा करना शुरू किया तो इस शख्स ने एसएचओ आशीष दुबे पर भी तलवार के हमला कर दिया। हमले में एसएचओ की गर्दन बाल बाल बची। इस दौरान गर्दन में लगी चोट के बाद रात में ही अस्पताल में एसएचओ को भर्ती कराया गया। इससे पहले भी सिंघु बॉर्डर पर एक और एसएचओ पर प्रदर्शनकारी निंहग द्वारा हमला किया जा चुका है, जिसमें उन्हें काफी चोट आई है। यह दूसरी बार है जब एसएचओ पर हमला किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में 22 फरवरी से दौड़ेंगी लोकल ट्रेनें, यूपी-हरियाणा के लोगों को होगा लाभ

नई दिल्ली। मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर रेलवे के अन्य मंडलों में लोकल यात्रियों की परेशानी दूर होगी। जल्द ही लोकल ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे को 35 लोकल ट्रेनें चलाने की अनुमति दे दी है। 22 फरवरी से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। सभी ट्रेनों को फिलहाल एक्सप्रेस का दर्जा देकर चलाने का फैसला किया गया है। इनमें दिल्ली से गाजियाबाद, पलवल, पानीपत सहित आसपास के अन्य शहरों के बीच भी लोकल ट्रेनें चलेंगी।

यात्री अनारक्षित टिकट लेकर इनमें सफर कर सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना होगा। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर के दैनिक यात्री लोकल व ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रेनें नहीं चलने से उन्हें अपने कार्य स्थल पर पहुंचने में दिक्कत होती है। उनके सामने सड़क से सफर करने का ही विकल्प है जिसमें समय और किराया दोनों ज्यादा लगता है। वहीं, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरने से सड़क मार्ग से दिल्ली आने जाने में परेशानी बढ़ गई है। दैनिक यात्रियों की इस परेशानी को देखते हुए उत्तर रेलवे ने पिछले दिनों रेलवे बोर्ड से लोकल ट्रेनें चलाने की अनुमति मांगी थी।

रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण के बीच जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए कुछ ट्रेनें चलाने की अनुमति दी है। इनमें 14 पैसेंजर ट्रेनें, पांच ईएमयू (इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट), दस एमईएमयू (मेनलाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट) और छह डीएमयू (डीजल मल्टीपल यूनिट) शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद इन ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इन्हें एक्सप्रेस ट्रेन का दर्जा दिया गया है। टिकट की बिक्री और रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 19 फरवरी को टैक्सी व बस मालिक करेंगे धरना-प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है। दिल्ली में भी पेट्रोल 90 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 80 रुपये प्रति लीटर पहुंचने के करीब है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बुधवार को लगातार 9वें दिन इजाफा किया है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 89.54 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का दाम 79.95 प्रति लीटर पहुंच गया है। गौरतलब है कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। वहीं, पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। इस कड़ी में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों तथा ट्रैफिक चालान के समेत अन्य मुद्दों को लेकर टैक्सी व बस मालिक व चालक 19 फरवरी को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया कि लंबे समय से दिल्ली के टैक्सी व बस मालिकों का आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण हो रहा है। लाखों रुपये के ट्रैफिक चालान किए जा रहे हैं। लोक अदालत के नाम पर भी तंग किया जा रहा है। संजय सम्राट ने कहा कि पिछले कई महीने से डीजल व पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं।

ताहिर हुसैन समेत 18 आरोपितों की हिरासत एक मार्च तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली दंगे में के आरोपित ताहिर हुसैन, उमर खालिद, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, इशरत जहां व शरजील इमाम सहित 18 आरोपितों की न्यायिक हिरासत कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक मार्च तक बढ़ा दी है। मंगलवार को यूएपीए के तहत गिरफ्तार 18 आरोपितों की हिरासत अवधि पूरी हो रही थी।

हिरासत पूरी होने पर आरोपितों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट में पेश किया गया। पिछली पेशी में कई आरोपितों ने कोर्ट से शिकायत की थी कि उन्हें जेल के अंदर आरोपपत्र की कापी नहीं दी जा रही है। जेल के जिस कंप्यूटर में कापी अपलोड है उस पर कोई न कोई बैठा रहता है। मंगलवार को हुई पेशी में पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने पेन ड्राइव में नताशा नरवाल को आरोपपत्र की कापी दी थी, वे उस पेन ड्राइव को वापस नहीं कर रही हैं। इस पर नताशा के वकील ने कहा कि वे जल्द इस पर जवाब देंगे। दिल्ली दंगे में आरोपित बनाए गए कैब चालक मोहम्मद दानिश को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। दानिश को दंगे के दौरान हुई एक पुलिसकर्मी रतनलाल की मौत मामले में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि चालक की कॉल डिटेल रिकॉर्डस (सीडीआर) के अनुसार वह उस इलाके के आसपास भी नहीं था, जहां दंगा हुआ था। पीठ ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए कोई सीसीटीवी फुटेज या वायरल वीडियो नहीं है। उक्त टिप्पणी के साथ पीठ ने आरोपित चालक को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

बिच्छू ने काटा तो साबुन से गढ़ दी उसी की आकृति, विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार ने सुनाई कलाकृतियों की कहानी

नई दिल्ली। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने 'कलम' (अपनी भाषा अपने लोग) कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मभूषण राम वंजी सुतार के साथ उनकी बनाई गई मूर्तियों के बारे में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। दैनिक जागरण, श्री सीमेंट व अहसास वूमन आफ एनसीआर के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में कथक नृत्यांगना शिंजिनी कुलकर्णी ने राम वंजी सुतार से उनके मूर्ति बनाने के सफर की शुरुआत से लेकर विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टेच्यू आफ यूनिटी बनाने तक के सफर पर चर्चा की। राम वंजी सुतार ने बताया कि उनके नाम के पीछे जो सुतार है उसका मतलब 'बढ़ई' होता है। उनके मूर्ति बनाने की कला के पीछे एक कारण यह भी रहा है। उन्होंने बताया कि वे 1948 से मूर्तियां बना रहे हैं। उनके बेटे अनिल का 1957 में जन्म हुआ।

वह भी स्कूल और कालेज के जमाने से ही उनके साथ मूर्तियां बना रहा है। वह एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है। जेजे स्कूल आफ आर्ट्स में जब उन्होंने दाखिला लिया तो शिक्षक ने पहले ही साल में देखा कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो सीधे उन्हें सेकेंड ईयर में भेज दिया। 1950 में गोल्ड मेडल भी मिला। बचपन में उन्हें एक बिच्छू ने काटा था। उन्होंने उस बिच्छू को मार दिया। फिर उसे देखकर साबुन से एक बिच्छू बना दिया। वहीं से उनके मूर्ति बनाने के सफर की शुरुआत हुई। चंबल देवी की मूर्ति बनाने का किस्सा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि 1960 में उन्हें मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध के लिए चंबल नदी को समर्पित करते हुए मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट मिला। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ती है। इसलिए उन्होंने चंबल नदी की प्रतीकात्मक मूर्ति को मां के रूप में दर्शाते हुए उसके साथ दो बच्चे बनाए, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भाईचारे के प्रतीक हैं। यह मूर्ति 45 फीट ऊंची है। उस समय यह उनके करियर का सबसे बड़ा काम था। इस मूर्ति के उन्हें 10 हजार रुपये मिले थे। सुतार ने कहा कि अब तक उन्होंने जितने भी राजनेताओं की मूर्तियां बनाई हैं, उनमें सबसे पसंदीदा मूर्ति महात्मा गांधी की है और सबसे मुश्किल भी उसे ही बनाना था। उन्होंने पहली व सबसे अधिक मूर्तियां महात्मा गांधी की ही बनाई हैं। उन्होंने कहा कि वे सिग्नेचर स्टाइल में मूर्तियां बनाते हैं। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में सीमेंट से गांधी जी की मूर्ति बनाई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को झटका

नई दिल्ली।

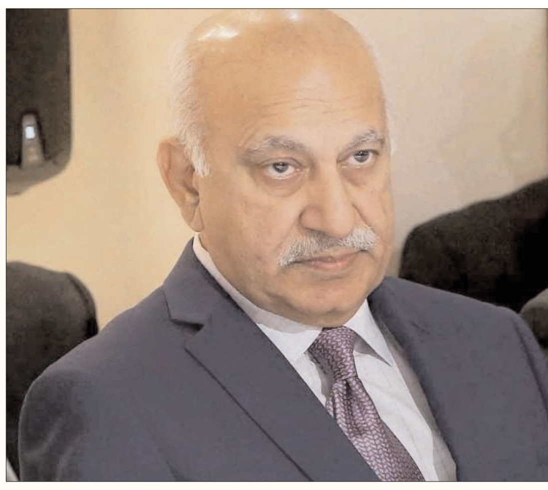

भारत में कई लोग सामने आए, जिन्होंने अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ कर्मियों पर शोषण के आरोप लगाए। इस क्रम में पत्रकार प्रिया रमानी ने साल 2018 में मीटू अभियान के दौरान एमजे अकबर पर शोषण का आरोप लगाया था। आरोपों के चलते राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर, 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

मीटू मामले में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने-माने पत्रकार एमजे अकबर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक ओपन कोर्ट में यह निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। साथ ही यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि देश के जाने माने पत्रकार एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी पर आपराधिक मानहानि का दावा किया था। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और पिछली सुनवाई में जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर बुधवार को निर्णय सुनाया है।

पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर की तरफ से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने फैसला 17 फरवरी के लिए टाल दिया था। इससे पहले 1 फरवरी को भी अदालत ने 10 फरवरी के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, कुछ साल पहले कई देशों में MeToo अभियान चला था।

इसमें नामी हस्तियों ने शारीरिक शोषण समेत कई अन्य आरोप पुरुषों पर लगाए थे। इसी कड़ी में भारत में कई लोग सामने आए, जिन्होंने अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ कर्मियों पर शोषण के आरोप लगाए।

इस क्रम में पत्रकार प्रिया रमानी ने साल 2018 में मीटू अभियान के दौरान एमजे अकबर पर शोषण का आरोप लगाया था। आरोपों के चलते राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर, 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं। इसके बाद अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।

पत्रकार प्रिया रमानी के मुताबिक, 20 साल पहले जब अकबर एक अखबार के संपादक थे, इस दौरान अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हुए शोषण किया।

दिल्ली में अब 100 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे सरकारी दफ्तर

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। दिल्ली में तो अब रोजाना 150 से भी कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने किसी कर्मी के कोरोना होने पर कार्यालय को सील नहीं करने का आदेश जारी कर दिया है। पिछले दिनों कोरोना के मामलों में कमी आने पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह निर्देश दो दिन पहले जारी किया था, जिसे मंगलवार से ही दिल्ली सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए कार्यालय आना आवश्यक कर दिया है। नए नियमों के अनुसार कार्यालय में अगर एक या दो व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उनके बैठने के स्थान तथा 48 घंटे के भीतर वे जहां-जहां गए हैं, उन इलाके को संक्रमण मुक्त करना होगा।

किस-किसको मिला 8 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपये का फ्लैट, 5 मार्च को चल जाएगा पता

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय योजना- 2021 में आखिरी दिन यानी मंगलवार को आधी रात तक आवेदन होते रहे। शाम छह बजे तक 1,354 फ्लैटों के लिए 31,000 से अधिक आवेदन डीडीए को मिल चुके थे। इनमें से 19,972 लोगों ने रजिस्ट्रेशन राशि का भुगतान भी कर दिया था। संभावना है कि आवेदकों की संख्या 32 हजार पार पहुंच जाए। डीडीए के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, फ्लैटों के लिए ड्रॉ लॉटरी के जरिये पांच मार्च को निकाला जाएगा। जानकारी के मुताबिक एलआइजी फ्लैटों के लिए 4,392 लोगों ने 25,000 रुपये का भुगतान किया। वहीं, एमआइजी फ्लैटों के लिए 2,114 लोगों ने 1,00,000 रुपये की राशि का भुगतान किया और एचआइजी फ्लैटों के लिए 13,466 लोगों ने 2,00,000 रुपये का भुगतान किया। अंतिम दिन पांच हजार से अधिक आवेदन आए हैं। डीडीए को

मालूम हो कि एचआइजी और एमआइजी फ्लैटों के लिए आवेदन शुल्क दो लाख रुपये है। एलआइजी फ्लैटों के लिए एक लाख रुपये, जबकि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 25,000 रुपये है।

अधिकतम 10,147 आवेदन शुल्क एचआइजी और एमआइजी फ्लैटों के लिए मिला है। 1,711 लोगों ने एलआइजी और 3,245 ने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए भुगतान किया है। मालूम हो कि एचआइजी और एमआइजी फ्लैटों के लिए आवेदन शुल्क दो लाख रुपये है। एलआइजी फ्लैटों के लिए एक लाख रुपये, जबकि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 25,000 रुपये है। कुल 1,354 फ्लैटों में से 254 एचआइजी फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 69.6 लाख रुपये से लेकर 2.1 करोड़ तक है। 757 एमआइजी फ्लैट हैं, जिसमें दो बेडरूम होंगे और इनकी कीमत 40.6 लाख से लेकर 1.4 करोड़ तक है। एलआइजी फ्लैट मात्र 52 हैं और ये एक बेडरूम वाले होंगे, जिनकी कीमत 17.7 लाख रुपये से लेकर 35.5 लाख रुपये तक होगी। वहीं, ईडब्ल्यूएस के 291 फ्लैट हैं। बता दें कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवेदन करने के चलते दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में भी लोगों का इतनी अधिक संख्या में आवेदन उत्साहित करने वाला है।

गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान नहीं जाएगा ट्रेन रोकने

नई दिल्ली। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद करने की मांग को लेकर दिल्ली-एनसीआर के चारों बॉर्डर (सिंघु, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर) पर बड़ी संख्या में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच आंदोलनकारी किसान बृहस्पतिवार को होने वाले रेल रोको आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। रेल रोकने पर राकेश टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा धरना-प्रदर्शन पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। रेल रोको आंदोलन के लिए धरना स्थल से कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। क्षेत्रीय लोग सांकेतिक रूप से ट्रेनें रोकेंगे और ड्राइवर को माला पहनाएंगे। इस दौरान यात्रियों को लस्सी के साथ खाना भी खिलाया जाएगा और उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वह आंदोलन में हमारा मौन समर्थन करें। बृहस्पतिवार को रेल रोको आंदोलन के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने साफतौर पर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कहा कि वह किसानों से न उलझे, यदि किसान अपने पर आए तो देश के सभी टोल फ्री कर दिए जाएंगे। वहीं, यूपी गेट पर जमा धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों के अगुवा राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल जाने का एलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत में पश्चिम बंगाल जाने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल जाकर वहां के किसानों की समस्या सुनेंगे और फिर केंद्र व प्रदेश सरकार से इस पर जवाब मांगेंगे। बता दें कि पश्चिमी बंगाल में अगले कुछ महीनों के दौरान विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राकेश टिकैत के जाने से वहां पर सियासत गरमा सकती है। यह अलग बात है कि वह किसानों के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सत्तासीन ममता बनर्जी सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोल सकते हैं।

विकास से ज्यादा जरूरी था लोगों की जान बचाना : गोपाल राय

नई दिल्ली। कैबिनेट मंत्री व आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि यह साल दिल्ली की जनता के साथ साथ हमारी सरकार के लिए भी चुनौतियों से भरा रहा है। एक साल पहले दिल्ली की सत्ता में जब फिर से हमारी पार्टी लौटी तो उसके तुरंत बाद ही उत्तर-पूर्वी जिले में दंगे हो गए। उससे हम लोग निपट ही रहे थे कि उसी दौरान कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ गया। मार्च के अंत में लाकडाउन लग गया। गोपाल राय के अनुसार, उस समय बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह थी कि जो गरीब हैं या जिनकी रोजी-रोटी छूट गई है, उन्हें कैसे बचाया जाए। आनन-फानन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बचाने के लिए वे सभी फैसले लिए जिससे गरीबों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। ऐसे में अगर कोई दिल्ली में विकास नहीं होने की बात कहता है तो बचकाना बयान है। हमारे लिए उस समय विकास की जगह लोगों की जान बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि पहले एक लाख, दो लाख, फिर चार लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, मगर जब लोगों की संख्या बढ़ती गई तो मार्च के अंत में 10 लाख लोगों के लंच व डिनर की प्रतिदिन व्यवस्था की गई। रहने के लिए स्कूलों में आश्रय गृह बनाए गए। एक करोड़ लोगों को राशन दिया गया। राय ने कहा कि महामारी फैली तो एक और चुनौती थी कि जो लोग संक्रमित हो रहे थे, उन्हें तुरंत इलाज मिले। कई अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित किए गए। बेड की संख्या बढ़ाई गई। प्लाज्मा बैंक शुरू किए गए। हल्के लक्षणों वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी गई। उन्हें आक्सीमीटर दिए गए। इस दौरान अक्टूबर में पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा। एक बार फिर कोरोना अधिक मजबूत होने लगा। इससे निपटने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। पूसा इंस्टीट्यूट के माध्यम से पराली के प्रदूषण को रोकने का फामरूला ढूंढा।

स्कूलों को मापदंडों के अनुरूप चलना होगा, क्लास में ही हो लंच की इजाजत

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण 19 मार्च, 2020 को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों की वापसी के लिए 11 महीने का लंबा इंतजार करना होगा। परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई हैं तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10वीं और12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। स्कूल भी खुल गए हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। हालांकि स्कूलों को अब बदले मापदंडों के अनुरूप ही चलना होगा। फिलहाल कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों के लिए ही स्कूल खुले हैं। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक एक कक्षा में मात्र 12-15 छात्रों को ही बैठने की

अनुमति है। एक्शन कमेटी आफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल संस्था ने बीते साल जुलाई-अगस्त में इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिया था। इसमें सभी दिशा निर्देशों को जारी करने से पहले छात्रों की सुरक्षा से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर विचार विमर्श भी किया गया। दरअसल सुरक्षा का मतलब केवल कोरोना से बचाव मात्र ही नहीं है, इसमें शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। बच्चे लंबे अंतराल से अपने मित्रों, अध्यापकों और विद्यालय से दूर हैं। इसके अलावा वे सीखने, पढ़ने और समझने की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में कमेटियों का गठन होना आवश्यक है। इन कमेटियों का काम बच्चों की समस्याओं की निगरानी और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हो। अक्सर लंच में बच्चे सहपाठियों के साथ ही खाना खाते हैं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि छात्रों को कक्षा में ही बैठकर लंच करने की अनुमति दी जाए। फिलहाल प्रार्थना सभा और अन्य शारीरिक गतिविधियों को प्रतिबंधित रखना ही उचित होगा। का सही से पालन हो इसके लिए शिक्षक से लेकर अन्य कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षिण देने की आवश्यकता है। बच्चे मानसिक तौर पर खुद को स्कूल आने में सुरक्षित महसूस कर सकें इसके लिए काउंसलर या सलाहकार अध्यापक का होना भी जरूरी है।

संपादकीय

अभी और कितना डराएगी महंगाई

बजट भी आ गया और क्रेडिट पॉलिसी भी। चारों तरफ धूम मची है कि वित्त मंत्री ने हिम्मत दिखाई, लोकलुभावन एलान करने के बजाय बड़े सुधारों पर जोर दिया। इससे आर्थिक तरक्की रफ्तार पकड़ेगी। रिजर्व बैंक ने भी इस नीति पर मोहर लगा दी है, और यह एलान किया है कि महंगाई फिलहाल काबू में है और आगे भी काबू में रहने वाली है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में कहा गया कि नवंबर में जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा 6.9 प्रतिशत था, वह दिसंबर में गिरकर 4.59 प्रतिशत हो चुका था। इसमें बड़ी भूमिका रही खाने-पीने की चीजों की कीमतों में आई कमी की। खाने-पीने की चीजों की महंगाई नवंबर के 9.5 फीसदी से गिरकर दिसंबर में 3.41 प्रतिशत पर पहुंच चुकी थी। मगर इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस मौसम में सब्जी की कीमत आसमान पर पहुंच जाती है और कब वह जमीन पर उतर आती है। फिर भी, रिजर्व बैंक का अनुमान है कि जनवरी से मार्च तक महंगाई दर 5.4 फीसदी रहेगी, अप्रैल से सितंबर तक यह 5.2 फीसदी से पांच फीसदी के बीच होगी, और सितंबर के बाद, यानी अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर में घटकर 4.3 प्रतिशत ही रह जाएगी। इसी भरोसे रिजर्व बैंक को लगता है कि ब्याज दरों में और कटौती की जरूरत नहीं है और वह बैंकों को नकदी रखने में दी गई छूट भी धीरे-धीरे वापस ले सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ने इस पॉलिसी से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में जो सर्वे किया है, उसमें शामिल परिवारों को महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है। रिजर्व बैंक अब हर दो महीने में ऐसा एक सर्वे करता है। इसमें यही पता लगाने की कोशिश होती है कि परिवार की शॉपिंग लिस्ट को देखते हुए इन परिवारों की महंगाई के बारे में क्या उम्मीदें या आशंकाएं हैं? इस बार के सर्वे में पिछले ऐसे सर्वेक्षणों के मुकाबले लोगों के मन में अनिश्चितता ज्यादा दिखाई पड़ी। अर्थ-नीति के तमाम विद्वान भी बजट को देखने के बाद कह चुके हैं कि अब हमें महंगाई के एक तगड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन उस तर्क पर जाने से पहले किसी भी आम आदमी के दिमाग में आने वाला सबसे बड़ा सवाल है, पेट्रोल और डीजल के दाम। आजादी के बाद कई दशक तक सरकार डीजल पर भारी सब्सिडी देती रही, क्योंकि यह माना जाता है कि डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई का बढ़ना लाजिमी है। आश्चर्य की बात यह है कि पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद इस पर कोई सुगबुगाहट तक सुनाई नहीं पड़ी। और ऐसा क्यों? जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव करीब 55 डॉलर प्रति बैरल हैं। जून 2008 में यही भाव 166 डॉलर तक चढ़ा था और उसके बाद भी कई साल 100 से 120 डॉलर के बीच झूलता रहा। जून 2014 में तो यह 115 डॉलर के करीब था और तब से इसमें लगातार गिरावट देखी गई। लेकिन भारत के बाजार में क्या हुआ? जून 2008 में जब कच्चा तेल 166 डॉलर का था, तब भारत में पेट्रोल 55.04 रुपये लीटर मिल रहा था। (अलग-अलग शहरों के भाव अलग हो सकते हैं।) और आज जब कच्चा तेल 55 डॉलर का एक बैरल है, तब मुंबई में पेट्रोल का दाम है 93.44 रुपये।

2014 में जब कच्चे तेल के दाम गिरने लगे, तब यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकारी तेल कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने तय किया कि दाम गिरने के साथ-साथ वह इन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती चलेगी। मतलब दाम जितना कम हुआ, उसका फायदा सरकार की झोली में चला गया। भारत में सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर साफ-साफ लिखा होता है कि आप जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा कहां जा रहा है। इसके हिसाब से 1 फरवरी को कंपनी दिल्ली में 86.30 रुपये का एक लीटर पेट्रोल बेच रही थी। इसमें से कंपनी का दाम और भाड़ा जोड़कर डीलर तक यह 29.71 रुपये में पहुंचा। 32.98 एक्साइज ड्यूटी और डीलर का कमीशन 3.69 रुपये। अब इस पर वैट लगा 19.92 रुपये, जो राज्य सरकार को मिलता है। यानी 30 रुपये से कम के पेट्रोल पर केंद्र सरकार करीब 33 रुपये और राज्य सरकारें करीब 20 रुपये टैक्स वसूल रही हैं। शुरू में केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि पिछले वर्षों में सरकार ने काफी सब्सिडी दी है और यह डर भी है कि आगे कच्चे तेल का दाम फिर बढ़ सकता है, इसीलिए सरकार दाम कम करने के बजाय टैक्स लगाकर एक रिजर्व फंड बना रही है, ताकि आगे चलकर दाम बढ़े, तो उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े। लेकिन अब जब कोरोना से मार खाए उपभोक्ताओं को राहत की जरूरत है, तो सरकार का हाल यह है कि एक्साइज ड्यूटी के खाते में कुल 3,35,000 करोड़ रुपये की कमाई में से 2,80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम पेट्रोल-डीजल के खाते ही चढ़ी हुई है। फिर, डीजल और पेट्रोल पर नया सेस या अधिभार लगने से भी लोग आशंकित हैं। हालांकि, सरकार ने कहा है कि इसका असर खरीदारों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कब तक नहीं पड़ेगा, यह सवाल बना हुआ है। डीजल और पेट्रोल से महंगाई बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक विशेषज्ञों को दूसरी चिंताएं भी सता रही हैं, एक, सेवाओं के दाम बढ़ने का डर, क्योंकि जैसे-जैसे बाजार में मांग बढ़ेगी, तरह-तरह के ऑपरेटर्स में अपनी फीस या रेट बढ़ाने की हिम्मत आएगी। और दूसरी, सरकारी खर्च और कर्ज में आनेवाली बढ़ोतरी से। शेयर बाजार के दिग्गजों का कहना है कि सरकार ने इस बजट में एक बड़ा दांव लगाया है, जिसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। सरकार यह रकम बाजार से उठाएगी, तो कर्ज का महंगा होना, यानी उस पर ब्याज बढ़ने का डर है। दूसरी तरफ अमेरिका जमकर नोट छाप रहा है, इसलिए महंगाई एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ऐसे में, सरकार के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या वह देश की तरक्की को बहुत तेजी से इतना बढ़ा सकती है कि लोगों को काम मिल जाए, उनकी आमदनी बढ़ जाए और वे थोड़ी-बहुत महंगाई बढ़ने की फिक्र से मुतमइन रहें? या फिर, कुछ ही समय बाद लोग विकास की चिंता छोड़कर 'हाय महंगाई' का नारा लगाते नजर आएंगे?

प्रवीण कुमार सिंह

भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे अभियान का उद्देश्य धन संग्रह नहीं, जन संग्रह

न्यास प्रत्येक दिन जमा होने वाली रकम का पूरा ब्योरा रख रहा है। इसके लिए समर्पित लोगों की टोली न्यास कार्यालयों में सतत सक्रिय है। चैक लेने से पूर्व उसमें लिखे ब्योरे की पूरी जांच निधि प्रमुख द्वारा बारीकी से की जा रही है जिससे उसे पास करने में बैंक को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चैक के पीछे दाता का नाम, पता व मोवाइल नंबर लिखवाया जा रहा है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर निधि प्रमुख या बैंक कर्मचारी उनसे सीधे संपर्क कर सके। यदि किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 80त्र के अंतर्गत छूट का लाभ लेना हो तो वह भी आसानी से उसे प्राप्त रसीद के द्वारा मिल सकेगा।

अयोध्या राम मंदिर को लेकर गत पाँच दशकों तक सतत संघर्ष चला। 76 युद्धों में लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया। लगभग 135 वर्षों की कानूनी लड़ाई तथा अनेक राज-सत्ताओं रामभक्तों तथा संतजनों के बलिदान के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामलला के पक्ष में आए अभूतपूर्व निर्णय ने विश्व इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है।

देश की स्वतंत्रता के उपरांत राम मंदिर के लिए चले आंदोलन के विभिन्न चरणों में शामिल लगभग 16 करोड़ लोगों की सहभागिता ने, इसे विश्व का सबसे बड़ा जन-आंदोलन बना दिया था। न्यायालय के निर्णय के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद आंदोलन का दौर समाप्त होकर भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक अभियान का दौर प्रारंभ हुआ है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार का धन संग्रह नहीं, बल्कि जन-संग्रह है।

इससे अधिकाधिक लोग भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर से तथा मंदिर भक्तों से सीधा जुड़ सकेंगे। इससे, वे गर्व से कह सकें कि यह मंदिर हमारा है। तभी तो ये सिर्फ राम मंदिर नहीं, अपितु एक राष्ट्र मंदिर कहलाएगा। यह अभियान ना तो दान का है, ना ही चंदे का, ना उगाही का है और ना ही बसूली का। यह तो भगवान को भक्त के श्रद्धापूर्वक समर्पण का पुनीत अभियान है।

भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बनने वाले भव्य-दिव्य श्रीराम मंदिर के लिए 15 जनवरी 2021 से एक महा-अभियान का शंखनाद हो चुका है। 27 फरवरी 2021 तक चलने वाले इस 44 दिवसीय श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत संपूर्ण भारत के सवा पाँच लाख गांवों के 13 करोड़

परिवारों से व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। देश की आधी जनसंख्या अर्थात लगभग 65 करोड देशवासियों तक पहुंचने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने समाज के लाखों सेवा-भावी व समर्पित बंधु-भगिनियों तथा संत समाज का सहयोग व आशीर्वाद लेते हुए लगभग 10 लाख टोलियों का गठन किया है। प्रत्येक टोली में 4 से 5 कार्यकर्ता लगे हैं। इस प्रकार लगभग 40 लाख कार्यकर्ता इस समय सम्पूर्ण भारत में राम-काज में लगे हैं। विधि सम्मत अधिकार देने हेतु न्यास ने एक अधिकार पत्र 15 नवंबर 2020 को जारी करते हुए ÷राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद तथा समाज के सम-विचारी विश्वसनीय बंधुओं÷ को इस कार्य हेतु अधिकृत किया।

प्रत्येक टोली में एक निधि प्रमुख (डिपॉजिटर) है। इस निधि प्रमुख को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा अधिकृत बैंक कोड दिया गया है। इस कोड के माध्यम से वह अपने आस-पास के समाज से एकत्र समर्पण राशि को सुगमता से अपने निकटतम बैंक में जमा करा रहे हैं।

न्यास ने समाज व समाज-सेवियों की सुगमता की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की देश-व्यापी सभी शाखाओं में निधि स्वीकार करने की व्यवस्था की है। प्रत्येक निधि प्रमुख को अपनी सुविधानुसार अपने निकट की किसी एक बैंक की किसी एक शाखा को चुन कर उसी में सम्पूर्ण निधि आरंभ से समापन तक जमा करनी है।

श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान हेतु जनता अपना समर्पण दो प्रकार से दे सकती है। एक तो सीधे बैंक से बैंक फंड ट्रांसफर/हृश्वस्न्ञ्ञ/ऋञ्जत्स के द्वारा तथा दूसरा व्यक्तिगत नगदी या चैक द्वारा। पहले केस में व्यक्ति को पैसा स्वयं अपने बैंक खाते से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के खाते में सीधा जमा करने से पूर्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बैंक विवरण को न्यास की वेबसाइट, फेसबुक व ट्विटर हैंडल से ठीक से मिलान करने के पश्चात ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा रहे कि समर्पणकर्ता यह कार्य न्यास की वेवसाइट के माध्यम से ही करे। किन्तु, फंड ट्रांसफर करने से पूर्व कृपया उसके बैंक विवरण की ठीक से जांच अवश्य करें।

दूसरे केस में जब निधि नगद, चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देनी हो तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद व हिंदू समाज के कार्यकर्ता घर-घर पहुँच रहे हैं। टोलियों में लोगों से दाता की इच्छानुसार समर्पण स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन, वह समर्पण किसी भी स्थिति में बिना कूपन या रसीद के नहीं होगा। यह कूपन या रसीद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ही उसके लोगो के साथ जारी की हुई है। प्रत्येक दाता समर्पण के उपरांत प्राप्त कर्ता से वह अधिकृत रसीद या कूपन अवश्य ले।

ये कूपन 10, 100 व 1000 रुपये के ही हैं। इससे अधिक की राशि हेतु रसीद है। 20,000 से अधिक की राशि चेक से ही ली जा रही है। प्राप्त समर्पण राशि को निधि प्रमुख द्वारा 48 घण्टे के अंदर न्यास के निकटस्थ बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अलावा कोई अन्य रसीद/कूपन या अन्य किसी भी माध्यम से एक नया पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। अभियान के समापन पर सम्पूर्ण देश में हर स्तर पर ऑडिट के माध्यम से एक-एक पैसे का हिसाब किताब बैंक खाते से मिलान कर न्यास को भेजा जाएगा।

यदि किसी को कोई शक या संशय हो, कूपन या रसीद की वैधता के संदर्भ में, तो उसका निराकरण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सीधा या श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान समिति के स्थानीय कार्यालय या प्रांत कार्यालय से निस्संकोच संपर्क किया जा सकता है। जिन खातों में पैसा जमा किया जा रहा है उनमें से धन निकासी का अधिकार किसी को भी नहीं है। वे सिर्फ जमा खाते हैं। इन खातों की कोई चैक बुक भी जारी नहीं हुई जिससे कोई कुछ गड़बड़ी कर सके।

न्यास प्रत्येक दिन जमा होने वाली रकम का पूरा ब्योरा रख रहा है। इसके लिए समर्पित लोगों की टोली न्यास कार्यालयों में सतत सक्रिय है। चैक लेने से पूर्व उसमें लिखे ब्योरे की पूरी जांच निधि प्रमुख द्वारा बारीकी से की जा रही है जिससे उसे पास करने में बैंक को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चैक के पीछे दाता का नाम, पता व मोवाइल नंबर लिखवाया जा रहा है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर निधि प्रमुख या बैंक कर्मचारी उनसे सीधे संपर्क कर सके। यदि किसी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की धारा 80त्र के अंतर्गत छूट का लाभ लेना हो तो वह भी आसानी से उसे प्राप्त रसीद के द्वारा मिल सकेगा। न्यास को आयकर विभाग द्वारा इसके लिए अधिकृत किया जा चुका है।

किसी भी सूरत में रद नहीं होने चाहिए कृषि कानून

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के आसपास कई जगह कथित किसान इन दिनों आंदोलनरत हैं। कुछ किसान संगठन प्रायोजित भीड़ द्वारा सामान्य नागरिकों का जन जीवन अस्त-व्यस्त किए हुए हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के प्रयासों को विफल करते हुए यह भीड़ हठवादिता पर उतार गई है। इसने गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर देश की प्रतिष्ठा को तार-तार करने का कुत्सित प्रयास भी किया। पूरे देश ने देखा कि टैक्टर रैली के दौरान उपद्रवियों की भीड़ ने किस तरह लाल किले पर अराष्ट्रीय ध्वज तक फहरा दिया।

संविधान के स्तंभों में विधायिका का अपना महत्व है। राष्ट्रीय महत्व के कानून बनाना उसका कर्तव्य है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाने के विषयों की अलग-अलग सूचियां हैं। इसमें एक समवर्ती सूची भी है, जिसपर दोनों अपने-अपने कानून बना सकते हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य, दोनों ही अपने-अपने विधेयक पारित करते हैं और दोनों में कोई विसंगति होती है तो केंद्रीय कानून से भिन्नता की सीमा तक प्रांतीय कानून शून्य माना जाता है। यानी केंद्रीय कानून का उपरिगामी प्रभाव होता है। कृषि समवर्ती सूची में है। ऐसे में केंद्र ने उस पर कानून बनाकर कोई संविधान विरोधी कार्य नहीं किया है। पांच वर्ष के लिए जनादेश पाई सरकार यदि कानून भी न बना पाएगी तो क्या करेगी? हर विधान पारित करने से पहले जनमत संग्रह तो किया नहीं जाता! क्या देश में पहले की सरकारें विधेयक नहीं पारित करती थीं? देश का हताश और निराश विपक्ष भाड़े की भीड़ एकत्र करके संविधान सम्मत सरकार को अस्थिर करने का ही कुचक्र कर रहा है, जो एक तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य है।

तीनों कृषि कानून देश भर के लिए हैं। देश के अधिकांश भागों में शांति है और किसान इन कानूनों से संतुष्ट हैं। सवाल है कि दिल्ली के आसपास ही बवाल क्यों? दिल्ली देश की राजधानी है और बगल के राज्यों-पंजाब तथा राजस्थान में विपक्ष की सरकारें हैं। दिल्ली की प्रदेश सरकार के मुखिया तो हर बात में केंद्र विरोधी नीति ही अपनाते हैं। इसके अलावा पंजाब की भूमि का बड़ा भाग वहां के कुछ नेताओं के अधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से है। कागज पर मालिक बने किसान मजदूर ही हैं। अतः उन्हें इन कानूनों से दिक्कत तो होगी ही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी एक जाट नेता को उत्तराधिकार में 12 बीघा जमीन मिली थी, पर आज वह दो सौ बीघे के स्वामी हैं। जाहिर है इन्हें भी कृषि कानूनों में खामी ही दिखाई पड़ेगी। इन दिनों किराये की भीड़ जुटाना कोई कठिन काम नहीं है। खास तौर पर सरकारों और पैसे वाले दबंगों के लिए। ऐसी जगहों पर जुटे लोगों में अधिकांश को वहां एकत्र होने का उद्देश्य ही नहीं मालूम होता है। प्रशासनिक पदों पर रहते हुए मैंने एक बार एक आंदोलन में आए कुछ लोगों से जब उनके आने का उद्देश्य पूछा तो उन्होंने एक आंचलिक नेता का नाम बताते हुए कहा कि अमुक ने कहा था 'चलो तकावी बट रही है, ले लो चलकर। गाड़ी तैयार है।'

विपक्ष को संसद में इन कानूनों पर सार्थक बहस करनी चाहिए। अराजकता फैलाकर जनजीवन से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। वहीं केंद्रीय सरकार को किसी भी सूरत में इन तीनों कानूनों को निरस्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर देश में नए कानून बनाना कठिन हो जाएगा। फिर लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी हो जाएगी। इससे देश में ऐसी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

डेटा ट्रैफिक से आगे

इसी हफ्ते नोकिया की ओर से जारी एक स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में डेटा ट्रैफिक में 60 गुना बढ़ोतरी हुई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी सामने आया है कि 5जी टेक्नॉलजी भले ही अभी भारत में न आई हो, लेकिन 5जी डिवाइस खरीदने वालों की देश में कोई कमी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अपने यहां अभी ही 20 लाख ऐसी डिवाइस मौजूद हैं। इससे अंदाजा मिलता है कि मोबाइल टेक्नॉलजी में हो रहे बदलावों को लेकर देशवासियों में कितना उत्साह है। हालांकि पांच वर्षों के अंदर डेटा ट्रैफिक में 60 गुना बढ़ोतरी के पीछे कई फैक्टर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सबके घटते-बढ़ते प्रभावों के बीच भी यह रुझान बढ़त पर ही जा रहा है। पिछले साल लॉकडाउन का दौर इसमें काफी मददगार साबित हुआ।

साल 2020 में डेटा ट्रैफिक में 36 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि वैक्सीन मिलने और कोरोना का फैलाव कम होने के बाद जैसे-जैसे स्कूल-कॉलेज और दफ्तर वगैरह खुलते जाएंगे, वैसे-वैसे डेटा यूज में कमी दर्ज की जा सकती है। लेकिन इस दौरान ओटीटी प्लैटफॉर्म की लोकप्रियता में आई उछाल और लोगों की ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन निपटाने की बढ़ी हुई आदत को रेखांकित करते हुए कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस ट्रेंड में जल्दी कोई उतार नहीं आने वाला। बहरहाल, ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस लगातार बढ़ते डेटा ट्रैफिक का नेचर कैसा है। इस लिहाज से गौर करें तो देश में इस्तेमाल हो रहा अधिकाधिक डेटा कन्ज्यूमिंग नेचर की गतिविधियों पर ही खर्च हो रहा है। इससे लोगों के दैनिक जीवन में थोड़ी गुणवत्ता जरूर आती है, लेकिन समाज की प्रॉडक्टिविटी बढ़ाने में खास मदद नहीं मिलती। इसे नापने का अच्छा तरीका यह देखना है कि इस डेटा का इस्तेमाल आम लोग अपनी कमाई बढ़ाने में कर पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से यूट्यूब जैसे मंचों ने आम लोगों को अपनी कला दिखाने के साथ-साथ कमाई करने का भी एक जरिया मुहैया कराया है, लेकिन इस्तेमाल हो रहे डेटा के अनुपात में ऐसे लोगों और उनके उत्पादों का दखल अभी भी बहुत कम है।

ध्यान रखना होगा कि यह बदलाव अपने आप नहीं होगा। कोई भी टेक्नॉलजी आती है तो उसे लाने वाली ताकतों का फोकस उससे खुद कमाई करने पर होता है। आम लोगों को कमाई का मौका देने वाली टेक्नॉलजी लाने या उपलब्ध टेक्नॉलजी को ही आम लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत पड़ती है। इसलिए अच्छा होगा कि बढ़ते डेटा ट्रैफिक पर खुश होने के बजाय हम अपना ध्यान इसके प्रॉडक्टिव इस्तेमाल को बढ़ावा देने के तरीके खोजने पर लगाएं।

जनता के भरोसे जोखिम उठाते पीएम मोदी, जो बन सकता है उनके लिए राजनीतिक घाटे का सौदा

यह बात तमाम दुनिया को नजर आ रही है। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनकी निंदा हीनभावना से उत्पन्न हुई है। जब आप कर्म के मामले में कमजोर होने लगते हैं तो निंदा आपके स्वभाव का स्थायी भाव बन जाती है। हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि-ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के मारे सो नहीं पाता। निरंतर अच्छा काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। हम और आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं।

किसी भी नेता की राजनीतिक पूंजी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। नेता इसका इस्तेमाल बड़ी किफायत से करते हैं और इसके प्रति सजग रहते हैं कि इसमें कमी न होने पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राजनीतिक पूंजी बहुत ज्यादा है, पर वह इसका इस्तेमाल बड़ी दरियादिली से करते हैं। लगता है उन्हें इसका अक्षय पात्र मिल गया हो। किसान आंदोलन के माहौल में कोई भी प्रधानमंत्री लोकलुभावन घोषणाओं का सहारा लेता। इसके विपरीत मोदी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। बजट के जरिये मोदी विकास की राजनीति की एक नई इबारत लिख रहे हैं। मोदी बड़ा राजनीतिक जोखिम मोल ले रहे हैं। वह एक के बाद एक नए-नए आर्थिक सुधार के ऐसे कदम उठा रहे हैं, जो राजनीतिक घाटे का सौदा बन सकते हैं। इन कदमों का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि ये विपरीत परिस्थितियों में उठाए जा रहे हैं। खराब परिस्थितियां केवल राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि कोरोना के कारण भी हैं।

मोदी के राजनीतिक विरोधियों के दो वर्ग हैं। एक दाएं-बाएं देखकर विरोध करता है। दूसरा, लगातार विरोध में लगा रहता है। मोदी का विरोध बाहर ही नहीं घर में भी है। संघ परिवार के विभिन्न अनुषंगिक संगठनों में से कोई एक समय-समय पर विरोध की आवाज बुलंद करता ही रहता है। किसानों के नाम पर चल रहा आंदोलन पहले अहिंसक से हिंसक हुआ और फिर गैर-राजनीतिक से राजनीतिक। विरोध के

इस वातावरण में किसी भी सरकार के हाथ-पांव फूल सकते हैं। विरोध का आलम यह है कि तिरंगे के अपमान के साथ गणतंत्र दिवस एवं लाल किले की मर्यादा तार-तार करने और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला करने वालों का भी समर्थन किया जा रहा है।

आपने इससे पहले देश में कोई ऐसा आंदोलन देखा है, जिसमें चार सौ पुलिस वाले घायल हो जाएं, उन पर लाठी, डंडे, लोहे के रॉड से ही नहीं तलवार से भी हमला हो और ऐसा करने वाले सीना तान कर घूम रहे हों। जैसे पीड़ित ही दोषी हों। ट्रैक्टरों को अभी तक हमने खेतों में चलते देखा था। 26 जनवरी को उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हुए भी देखा। विरोधियों के हिसाब से यह सब जायज है, क्योंकि वह मोदी के विरोध में है। मोदी इन सबसे कतई विचलित नहीं लगते। अपने समर्थकों और देश के आमजन की सहज बुद्धि पर शायद ही किसी प्रधानमंत्री को ऐसा भरोसा रहा हो। उनके मन में यह बात बहुत गहरे बैठी हुई है कि लोग ईमानदार आदमी का साथ देते हैं।

भारतीय समाज के मानस में एक बात गहरे पैठी हुई है कि ईमानदार आदमी अच्छा होता है और वह व्यक्तिगत स्वार्थ पर समाज के हित को वरीयता देता है। इसीलिए विपक्ष के इतने बड़े नेताओं के होते हुए भी उन्हें 1975 में एक जयप्रकाश नारायण, 1986-87 में एक वीपी सिंह और 2011 में एक अन्ना हजारे की जरूरत पड़ी। इन तीनों अवसरों पर सत्तारूढ़ दल और उसके नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के आरोप थे।

जनमानस में उनकी विश्वसनीयता नहीं रह गई थी और लोकप्रियता निचले पायदान पर थी। जेपी, वीपी और अन्ना के सफल होने का यह एक बहुत बड़ा कारण था। विपक्ष के दुर्भाग्य से उसके सामने ऐसा कोई नेता नहीं है। देश के सौभाग्य से वर्तमान सरकार का नेतृत्व ईमानदारी की मिसाल है। उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता कम होने के बजाय बढ़ी ही है। मोदी से पहले केवल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो सत्ता में आने के बाद भी विश्वसनीय और लोकप्रिय बने रहे।

कहावत है कि अच्छी अर्थनीति खराब राजनीति होती है और अच्छी राजनीति खराब अर्थनीति। मतलब यह कि दोनों को एक साथ नहीं साध सकते, पर ऐसा लगता है कि मोदी 'एकै साधे सब सधें, सब साधे सब जाए' की नीति में विश्वास करते हैं। पिछले करीब पौने सात सालों ने यह दिखाया है कि अर्थनीति हो या राजनीति, फैसले अच्छी नीयत से किए जाएं तो नतीजा अच्छा ही निकलता है। जब-जब संकट की घड़ी आई, मोदी ने देश के लोगों पर भरोसा किया और देशवासियों ने मोदी पर। नेता और जनता के इस परस्पर भरोसे की तुलना कुछ हद तक जवाहरलाल नेहरू के समय से की जा सकती है। तब कांग्रेस के लोग मानकर चलते थे कि नेहरू जो कहेंगे, देश उसी को सच मानेगा। लोग मानकर बैठे हैं कि दर्द कितना भी बड़ा हो, उसकी दवा मोदी के पास है।

लगभग चार दशक से मैं भारतीय राजनीति को करीब से देख रहा हूं। मुझे याद नहीं कि विपक्ष कभी इतना निस्तेज और साख विहीन रहा हो। यह स्थिति जनतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वास्तविकता को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकार के खिलाफ मुद्दा हो तो विपक्ष की ताकत बढ़ती है, पर यह भी सही है कि मुद्दे केवल अवसर देते हैं। अवसर का लाभ उठाने के लिए विश्वसनीयता जरूरी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कविता का उद्धरण दिया। इस कविता का अर्थ था कि चिड़ियों को पौ फटने से पहले ही रोशनी का आभास हो जाता है और वे चहचहाने लगती हैं।

कोरोना महामारी से देश जिस तरह निपटा, चीन को सीमा पर जिस तरह का जवाब दिया गया, वैक्सीन के विकास और टीकाकरण में जिस तरह की शुरुआत हुई और अब बजट के जरिये आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह की पहल हुई, वह नए भारत के अभ्युदय का संकेत है। मोदी ने न केवल इस संकेत को पहचान लिया है, बल्कि इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। आने वाला समय भारत का है और उसके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह बात तमाम दुनिया को नजर आ रही है। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनकी निंदा हीनभावना से उत्पन्न हुई है। जब आप कर्म के मामले में कमजोर होने लगते हैं तो निंदा आपके स्वभाव का स्थायी भाव बन जाती है। हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि-ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के मारे सो नहीं पाता। निरंतर अच्छा काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। हम और आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

जीतन राम मांझी ने विधान परिषद की एक और सीट पर दावा ठोंका, बिहार में एनडीए की बढ़ी मुश्किल

पटना । एनडीए में शामिल हम प्रमुख जीतन राम मांझी और वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी की नई-नई मांग ने एनडीए की मुश्किल बढ़ा दी है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने विधान परिषद की एक और सीट पर दावा ठोंका है। वे विधान परिषद की राज्यपाल कोटे से मनोनयन वाली सीट की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस कोटे की सभी 12 सीटें खाली हैं, जिन्हें जल्द भरा जाना है। खेल, कला संस्कृति, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करनेवाले लोगों का इन सीटों पर मनोनयन किया जाता है। मांझी और मुकेश सहनी ने पहले नीतीश मंत्रिमंडल में दो-दो मंत्री पद की मांग की थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी खाली हाथ रह जाने के बाद अब इनकी नजर विधान परिषद की सीट पर टिक गई है। बता दें कि कल ही वीआइपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी इन सीटों में से एक सीट की मांग वीआइपी और एक सीट की मांग हम के लिए की थी। दो मंत्री पद की मांग पूरी नहीं होने पर नाराज सहनी अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे। वहां से लौटते ही उन्होंने विधान परिषद की एक सीट की मांग रख दी। उन्होंने यह भी कहा कि वीआइपी और हम को विधान परिषद की एक-एक सीट देने का फैसला अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व को करना है। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जदयू का विधान परिषद की इन सीटों के लिए 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है। ऐसे में अब यह देखना है कि सहनी और मांझी की नई मांग एनडीए में क्या गुल खिलाती है।

मुजफ्फरपुर समेत 11 जिलों में पानी की तरह बहाए गए पैसे

मुजफ्फरपुर । बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कई जिलों के खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कई जिलों में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ढाई से तीन गुना अधिक खर्च हुआ है। समीक्षा में मामला सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने खर्च के बिल की गंभीरता से जांच के बाद ही भुगतान का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि भुगतान के पूर्व दावे एवं किए गए कार्य की जांच के आधार पर वास्तविक राशि का ही भुगतान हो। गड़बड़ी मिलने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। माना जा रहा है कि कोरोना के कारण पिछले वर्ष हुए चुनाव में बूथों की संख्या 25 फीसद बढ़ानी पड़ी थी। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया गया था। इस कारण विधानसभा चुनाव 2015 की तुलना में खर्च अधिक होना तय था। मगर समीक्षा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाया कि 11 जिलों मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, अरवल, कैमूर, गया, सहरसा, नवादा और जमुई में चुनाव खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। प्रमुख जिलों से दिए गए खर्च की जो जानकारी दी गई उसके अनुसार मुजफ्फरपुर में 57 करोड़ 44 लाख व्यय हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खर्च को अधिक बताया। जिले में वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में करीब 15 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे। सहरसा जिले से 10 करोड़ रुपये का आवंटन मांगे गए। समीक्षा में यहां भी खर्च अत्यधिक पाया गया। अरवल में महज दो विधानसभा के लिए छह करोड़ से अधिक के आवंटन में लगभग साढ़े चार करोड़ के व्यय को भी अत्यधिक खर्च माना गया। गया में लगभग 47 करोड़ के आवंटन की मांग की गई। यहां मॉडल बूथ के कारण अधिक खर्च की बात कही गई। मगर आयोग ने इसे अधिक खर्च बताते हुए बिलों की जांच के बाद ही भुगतान करने को कहा है।

जालंधर में अखिल विश्व गीता महामंडल का 51वां स्थापना दिवस मनाया, संकीर्तन मंडली ने भजन किए पेश

जालंधर । अखिल विश्व गीता महामंडल के 51वें स्थापना दिवस समारोह को लेकर शिव गोपाल मंदिर इमाम नासिर में समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक पंडित केवल कृष्ण शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में जिले भर से श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने भजनों के साथ सभी को मंत्रमुग्ध किया। समारोह का आगाज गुरु वंदना के साथ किया गया। इसके उपरांत पंडित केवल कृष्ण शर्मा ने कहा कि गीता के ज्ञान की अलख घर-घर जगाने के लिए अखिल विश्व गीता महामंडल का गठन किया गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह गीता जयंती महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष रवि शंकर शर्मा बताते हैं कि भागवत गीता, वेद उपनिषद व शास्त्रों के ज्ञान की उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए धार्मिक स्थानों में पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिल विश्व गीता महामंडल की ओर से वैदिक ज्ञान व संस्कृति का प्रचार व प्रसार करने के लिए पिछले 51 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान मां सरस्वती की पूजा अर्चना व वीर हकीकत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं संस्था की ओर से इस प्रयास में सहयोग देने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंदिर में गीता पुस्तकालय की स्थापना भी की गई। इस अवसर पर कमल टंडन, प्रमोद मल्होत्रा, पंडित सुरेश शास्त्री, अशोक शर्मा, मोहन लाल शर्मा, राहुल बाहरी, प्रवीण कोहली, यश पहलवान, सुरेश अरोड़ा, नरेंद्र शर्मा, राजन सोनी, हरीश शर्मा, दविंदर चोपड़ा, ज्योति प्रकाश व वरिंदर शर्मा काला मौजूद थे।

एनएच-74 घोटाला मामले के आरोपित चकबंदी अधिकारी की हार्ट अटैक से नैनीताल में मौत

नैनीताल । एनएच-74 घोटाला मामले की तारीख को लेकर नैनीताल पहुंचे पूर्व चकबंदी अधिकारी की हृदयाघात से मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से चमरसैना जिला जारौन झांसी निवासी हाल शुभम बिहार कालोनी जमालपुर कला हरिद्वार निवास गणेश प्रसाद निरंजन मंगलवार को अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ नैनीताल पहुंचे हुए थे। यहां वह 18 तारीख को कोर्ट में तारीख के सिलसिले में आए हुए थे। मंगलवार दोपहर पहुंचने के बाद उन्होंने नैना देवी मंदिर में दर्शन के बाद होटल में खाना खाया और कमरे में आराम करने चले गए। रात को होटल कर्मियों ने खाना खाने को लेकर पूछा तो उन्होंने तबियत खराब होने की बात कहकर मना कर दिया। रात करीब दस बजे अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जिस पर पत्नी ने पूर्व में चल रही दवाइयां उन्हें दी, लेकिन सुधार नहीं हुआ। एक घंटे बाद जब वह उल्टियां करने लगी तो होटल कर्मचारी और पत्नी उन्हें लेकर बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉ सुतांशु शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला हृदयाघात का मालूम पड़ रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का पता लग पाएगा। इधर सूचना के बाद कोतवाली एसआई हरीश सिंह शव के पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

विवादों में घिरी बोधि सोसाइटी, महासचिव की टीम ने उपाध्यक्ष को छह साल के लिए किया निष्कासित

जमशेदपुर । शहर की प्रमुख धार्मिक संस्था बोधि सोसाइटी भी विवादों में घिर गई है। इस सोसाइटी की महासचिव की टीम ने उपाध्यक्ष प्रकाश बरुआ को छह साल के लिए सोसाइटी से निष्कासित कर दिया है। इधर महासचिव प्रदीप बरुआ ने कहा कि गौतम बुद्धा सोशल वेलफेयर मिशन संस्था पर झूठा आरोप लगाया गया। इस संस्था ने बोधि सोसाइटी के फंड का दुरुपयोग नहीं किया है। बोधि सोसाइटी के नए गेट के मामले में निष्कासित उपाध्यक्ष प्रकाश बरुआ ने झूठा बयान दिया है। इसे लेकर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में सोसाइटी के अध्यक्ष मनोज हुमने, महासचिव प्रदीप बरुआ, उपाध्यक्ष अशोक बरुआ ने बताया कि प्रकाश कुसुम बरुआ के अतीत में भी ऐसे कई मामले है जो सोसाइटी में समाज की छवि धूमिल कर रही थी। इसका प्रमाण भी सोसाइटी के पास है। सोसाइटी ने उन्हें व उनके सहयोगियों को चेतावनी देते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि यदि भविष्य में इस तरह की वित्तीय अनियमितता की गतिविधियों में संलिप्त रहे तो उनके ऊपर बौधि सोसाइटी के संविधान के अनुसार उनकी आजीवन सदस्यता समाप्त की जाएगी और सख्त कानूनी कार्यवाही भी होगी।

यूपी बजट सत्र में योगी सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष ने कसी कमर

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होने वाला विधान मंडल का बजट सत्र हंगामेदार होगा। कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना संकट में बढ़ा भ्रष्टाचार, गन्ना मूल्य भुगतान न होने व किसानों के विभिन्न मुद्दे आदि लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की तैयारी तेज कर दी है।

बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को शाम सात बजे पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक आहूत की है। वहीं, समाजवादी विधायक 18 फरवरी को सुबह नौ बजे पार्टी मुख्यालय में एकत्रित होंगे और साइकिलों से विधान भवन की ओर कूच करेंगे। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी 18 को सुबह दस बजे होगी। मुख्यमंत्री योगी आादित्यनाथ की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक बुधवार शाम को होगी, जिसमें सत्र संचालन कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विधानसभा चुनाव से पूर्व योगी सरकार का अंतिम आम बजट होने के कारण जहां सत्ता पक्ष की ओर से जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें होंगी।

वहीं विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की हरसंभव प्रयास किया जाएगा। ध्वस्त कानून व्यवस्था, कोरोना संक्रमण काल में भ्रष्टाचार, विकास ठप होने व बढ़ती महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों के अलावा कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन की तपिश भी सदन में दिखेगी। नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी का कहना है कि हर मोर्चे पर फेल साबित हुई सरकार को सदन के भीतर और बाहर भी आईना दिखाया जाएगा। सरकार की नाकामियों से जनता में ही नहीं सत्ता पक्ष में भी भारी असंतोष है।

बहुजन समाज पार्टी के दलनेता लालजी वर्मा का कहना है कि जन अपेक्षाओं पर नाकाम रही सरकार अब जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है। बसपा

लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार की विफलताएं उजागर करेगी। विधान परिषद में कांग्रेस दलनेता दीपक सिंह का कहना है कि फ्लाप सरकार की विफलताओं को सदन के भीतर व सड़क पर मजबूती से उठाया जाएगा।

सर्वदलीय बैठक आज ः बजट सत्र को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आादित्यनाथ की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक 17 फरवरी को आहूत की गई है। इसी दिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक भी होगी, जिसमें विधानसभा सत्र संचालन कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने बताया कि सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हो गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के सभी कर्मियों की कोरोना जांच करा दी गई है। विधायकों की कोरोना जांच जारी है। सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए सभी कर्मियों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी।

मीडिया कर्मियों के लिए इस बार भी तिलक हाल में बैठने की व्यवस्था की गई है। सदस्यों को विधान भवन में आने-जाने के लिए निर्बाध व सुविधाजनक व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा के गेट पर सदस्यों और मीडिया कर्मियों के वाहनों की जांच व थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

विधायकों को पीना होगा काढ़ा ः कोरोना संक्रमण के बचाव उपायों का सख्ती से पालन किया जाएगा। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे का कहना है कि सदन के भीतर सदस्यों के बैठने की व्यवस्था सुरक्षित शारीरिक दूरी को ध्यान में रखकर की जाएगी। दर्शक दीर्घा में भी विधायकों को बैठना होगा। कोविड टेस्ट विधानसभा कर्मियों व अधिकारियों के साथ विधायकों के लिए अनिवार्य किया गया है। मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना होगा। विधानभवन की कैंटीन में विधायकों के लिए चाय, काफी के साथ काढ़ा पीने की व्यवस्था होगी। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम तक कराए गए सभी कोविड टेस्ट नगेटिव निकलें।

पेपरलेस बजट की तैयारी ः केंद्र सरकार की तरह प्रदेश में भी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने की तैयारी है। प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने बताया कि अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दोनों सदनों के सदस्यों को आइपैड-टेबलेट का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बजट को पटल पर रखने के साथ वेबसाइड पर डाउनलोड कर दिया जााएगा।

जहरीली शराब पीने से झारखंड के दो मजदूरों की मौत, गोपालगंज के ईंट भट्ठा पर करते थे काम

गोपालगंज । बिहार के गोपालगंज जिले में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत होने की खबर मिल रही है। आशंका जताई जा रही है कि शराब जहरीली थी। मरने वाले दोनों लोग झारखंड के मजदूर हैं, जो एक ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। इस मामले में एक और मजदूर का इलाज चल रहा है। पूरी घटना विजयीपुर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में हुई है। इसी तरह का मामला इसी महीने में बिहार के कैमूर जिले में सामने आया था, जहां तीन लोगों की मौत हो गई थी।

बताया जा रहा है कि शराब पीने से ईंट भट्ठा पर काम कर रहे झारखंड के दो मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। भट्ठा पर काम करने वाले मजदूरों ने देर रात दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों मजदूरों की सुबह मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर एसडीओ उपेंद्र पाल सदर अस्पताल पहुंच गए हैं। हालांकि प्रशासन यह कहते हुए जहरीली शराब पीने से मजदूरों की मौत होने की बात स्वीकार नहीं कर रहा है कि मामला संदिग्ध है। जांच के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुख्ता तौर पर मौत की सही वजह सामने आ सकेगी।

मठिया गांव में शराब पीने के बाद लौटते ही बिगड़ी तबीयत

बताया जाता है कि झारखंड के गुमला जिले के भरना दिशा के मरसिल गांव निवासी बोधवान पन्ना यदि कर्मा पन्ना विजयीपुर के मझवलिया में स्थित एक ईंट भट्ठा पर मजदूरी करते थे। दोनों मजदूर मंगलवार की रात नजदीक के मठिया गांव में शराब पीकर ईंट भट्ठा पर लौट। कुछ देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई।

देर रात साथी मजदूरों ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीओ उपेंद्र पाल सदर पहुंच गए हैं। एसडीओ ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है। जांच के लिए डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि दोनों मजदूरों की मौत शराब पीने से हुई है या किसी अन्य कारण से।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में मिला नोटों से भरा बैग, इतना रुपया कि रात 12:15 बजे तक चली गिनती

कानपुर । नई दिल्ली से जयनगर बिहार जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस जब सोमवार रात कानपुर सेंट्रल पहुंची तो उसके पैंट्रीकार में नोटों से भरा बैग मिला। पहले तो मंगलवार को यह खबर बाहर ही नहीं आने दी गई, लेकिन रात करीब आठ बजे रेलवे के अफसरों ने इसकी जानकारी तो आधा मामला सामने आया। इसके बाद जीआरपी ने आयकर विभाग को सूचना दी। पहले तो अफसरों में इस बात की चर्चा रही कि ताला लगा होने के कारण बुधवार तक नोटों की गिनती हो सकेगी, लेकिन मंगलवार देर रात 12ः15 पर ही नोटों की गिनती पूरी हो गई। बता दें कि अब तक बैग पर किसी ने दावा नहीं पेश किया है।

नई दिल्ली से आकर कानपुर सेंट्रल पर रुकी थी ट्रेन - नई दिल्ली से जयनगर जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोविड स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से सोमवार रात 9:15 पर चली और देर रात 2:51 पर कानपुर सेंट्रल पहुंची। इसी दौरान पैंट्रीकार के कर्मचारियों ने रेलवे अफसरों को ट्रेन में लाल रंग का ट्रॉली बैग काफी देर से पड़े होने की सूचना दी। जिसके बाद जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम वहां पहुंची और स्कैनिंग करने के बाद जीआरपी ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटनाक्रम के चलते 19 मिनट बाद रात 3ः10 पर ट्रेन को जयनगर के लिए रवाना कर दिया गया। बैग की स्कैनिंग के दौरान उसमें नोट होने की जानकारी जीआरपी और आरपीएफ को हो गई थी लेकिन शाम तक नोटों से भरे बैग की कहानी छिपाए रखी गई।

देर रात 12:15 पर पूरी हुई नोटों की गिनती - सभी कोई इस बात को लेकर आशंकित था कि नोटों की गिनती बुधवार को संभव हो सकेगी, लेकिन रात 12:15 पर नोटों की गिनती पूरी हुई। इसमें कोई दोराय नहीं कि मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया गया। जीआरपी और रेलवे प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में हुई गिनती के दौरान लाल ट्रॉली बैग से कुल एक करोड़ 40 लाख रुपये बरामद हुए। इतनी बड़ी संख्या में धनराशि बरामद होने के बाद रेलवे के सभी अफसर सन्न रह गए।

उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने प्रियंका वाड्रा के मंच पर कसा तंज, बोले- किसान महापंचायत या मुसलमान...

मेरठ । पश्चिमी उप्र में किसान पंचायतों के बीच राजनीतिक टकराहट नया रंग ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बिजनौर में प्रियंका वाड्रा के मंच पर मुस्लिम चेहरों की संख्या को लेकर तंज कसा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और मुजफ्फरनगर प्रभारी डा. चंद्रमोहन के ट्वीट के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रियंका वाड्रा के बिजनौर कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कांग्रेस के मंच पर राशिद अलवी, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नूरबानो और शेरबाज खान को मौजूद देख इसे मुसलमान पंचायत बताकर पश्चिमी उप्र का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। इस ट्वीट के आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सांप्रदायिक ट्वीट बताते हुए भाजपा पर सवालों की बौछार की। दूसरी ओर, पांच फरवरी को रचित चौधरी नामक युवक की हत्या पर भी भाजपा ने कांग्रेस और रालोद को घेरा है।

दागे सवाल, रचित के घर क्यों नहीं गईं प्रियंका- पांच फरवरी को बिजनौर शहर कोतवाली अंतर्गत सिहोरा क्षेत्र में गिरधर निवासी 25 साल के रचित चौधरी की हत्या को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पांच लाख रुपये की सहायता राशि भेंट की। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डा. चंद्रमोहन ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के वहां न जाने को लेकर भी सवाल खड़ा कर दिया।

रचित के घर भाजपा के कई नेता पहुंच सकते हैं

जाट युवक की हत्या में विशेष समुदाय के कई युवकों की धरपकड़ की गई है, जिसको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस और रालोद को घेर रही है। बहरहाल, आने वाले दिनों में भाजपा के कई बड़े नेता मृत रचित चौधरी के घर पहुंच सकते हैं। जिसके एक के बाद एक ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। वहीं एक भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल ने भी रचित जाट के घर न जाने पर प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधा। फिलहाल किसान पंचायत को लेकर सियासत जारी है।

बिना डॉक्टर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा दी तो होगी कार्रवाई, NHRC की नोटिस पर जवाबदेही तय

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि डॉक्टर की उपस्थिति के बिना मरीजों को दवा न दें। सभी सरकारी अस्पतालों को नोटिस भेजकर अलर्ट किया गया है कि यदि ऐसी शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीन साल पुराने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को आखिरकार जवाब भेज दिया गया। आयोग ने यह फाइनल रिमाइंडर भेजकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी थी कि वह इस प्रकरण पर ठोस कार्रवाई कर उसे सूचित करें।

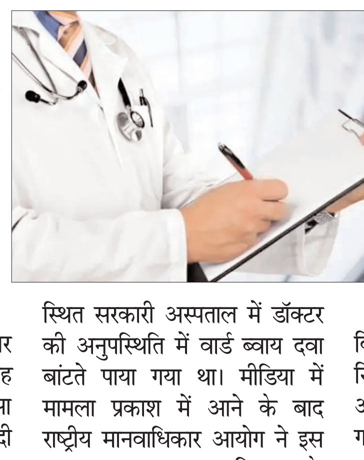

करीब तीन साल पहले जनवरी 2018 में बाराबंकी में सराय गोपी स्थित सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति में वार्ड ब्वाय दवा बांटते पाया गया था। मीडिया में मामला प्रकाश में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकरण पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक से जवाब मांगा लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। 26 नवंबर, 2020 को भी सख्त नोटिस जारी की गई मगर कोई जवाब नहीं मिला।

फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंतिम रिमांडर भेजते हुए 22 फरवरी 2021 तक मामले में हुई कार्रवाई और रोकथाम के लिए उठाए गए कदम के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव शिव गोपाल सिंह की ओर से मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर सूचित किया गया है कि ऐसे मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की ओर से सभी अस्पतालों को नोटिस भेजकर अलर्ट किया गया है।

महिलाओं पर परिवार नियोजन की जिम्मेदारी : चार साल में 11,343 महिलाएं और मात्र 78 पुरुषों ने कराया नसबंदी, उदासीनता

लखीसराय । कहने को तो महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार मिला हुआ है। महिला एवं पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है परंतु जमीनी सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। समाज में अभी भी पुरुषों की ही प्रधानता हावी है। पुरुषों में गलत धारना है कि नसबंदी कराने के बाद वे कमजोर हो जाएंगे। साथ ही वे नपुंसक भी हो जाएंगे। इसको लेकर पुरुष स्वयं नसबंदी नहीं कराकर महिलाओं का बंध्याकरण करा रहे हैं। यानि पुरुष प्रधान समाज में परिवार नियोजन की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर पर ही अब तक है। यही कारण है कि चार वर्षों में जिले में 11,343 महिलाओं ने बंध्याकरण कराया है जबकि मात्र 78 पुरुषों ने ही नसबंदी कराया है। इनमें से भी अधिकांश लोगों ने किसी बीमारी से ग्रस्त होने के बाद ही नसबंदी कराया है।

जबकि बंध्याकरण कराने वाली महिला से नसबंदी कराने वाले पुरुषों को अधिक प्रोत्साहन राशि मिलती है। नसबंदी कराने के लिए पुरुषों को प्रोत्साहित करने को लेकर सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नसबंदी कराने के बाद कमजोर एवं नपुंसक होने की पुरुष के मन से गलत-फहमी दूर करने को लेकर पुरुषों को जागरूक किया जा रहा है। नसबंदी कराने वाले पुरुष को प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन हजार रुपये एवं मोटिवेटर को चार सौ रुपये मिलता है। जबकि बंध्याकरण कराने वाली महिला को दो हजार व मोटिवेटर को तीन सौ रुपये मिलता है। वहीं प्रसव के एक सप्ताह के भीतर बंध्याकरण कराने वाली महिला को तीन हजार व मोटिवेटर को चार सौ रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है।

सिविल सर्जन डॉ आत्मानंद कुमार ने कहा कि पुरुषों में गलत धारना बनी हुई है कि नसबंदी कराने के बाद वे शारीरिक रूप से कमजोर एवं नपुंसक हो जाएंगे। यही कारण है कि पुरुष नसबंदी कराने से परहेज करते हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है। नसबंदी कराने वाले पुरुष न तो कमजोर होते हैं और न ही वे नपुंसक होते हैं। पूर्व की तरह ही वे सारा कार्य करते हैं। इसको लेकर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

पीएफआइ का चेहरा बेनकाब, दहशत का माहौल बनाने के आरोप में अब तक यूपी में 123 सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ । पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) का चेहरा देश के सामने बेनकाब हो गया है। लखनऊ में मंगलवार शाम गिरफ्तार पीएफआइ के कमांडर केरल निवासी अन्सद बदरुद्दीन और केरल के ही निवासी फिरोज खान के खौफनाक मंसूबे जान सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आतंकी हमलों को अंजाम देने के साथ इनके निशाने पर हिंदूवादी संगठनों के नेता थे, जिनकी हत्या कर देश में दहशत का माहौल बनाना था। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए विदेश से फंडिंग भी की गई है।

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हिंसा फैला चुके पीएफआइ के 123 सदस्यों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर उपद्रवियों ने यूपी में भी पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। लखनऊ में 23 दिसंबर 2019 को पुलिस ने हिंसा के मामले में पीएफआइ के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद समेत अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

हाथरस कांड के बाद सूबे में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश भी रची गई थी। इस मामले में मथुरा में पुलिस ने पीएफआइ की स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था। चारों से पूछताछ में साजिश के मास्टमाइंड सीएफआइ के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ अहमद की भूमिका सामने आई थी, जिसे बाद में 12 दिसंबर 20120 को तिरुवंतपुरम एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। एसटीएफ व ईडी दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। ईडी आरोपितों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। वहीं एसटीएफ ने रऊफ को केरल से गिरफ्तार कर

मथुरा की कोर्ट में पेश किया था। यूपी पुलिस ने सीएए के विरोध में हिंसा की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार को पत्र भेजकर पीएफआइ संगठन को सिमी की भांति प्रतिबंधित किए जाने की सिफारिश की थी। सिमी के कई पदाधिकारी व सक्रिय सदस्यों के पीएफआइ से जुड़े होने की बात भी सामने आ चुकी है।

एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि 17 फरवरी को पीएफआइ का स्थापना दिवस है। आशंका है कि संगठन के सदस्य कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। इसे देखते हुए बुधवार को उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पीएफआइ ने इंटरनेट मीडिया पर संदेश चलाकर यह भी स्वीकार किया है कि मथुरा में पकड़े गए सीएफआइ सदस्य हाथरस जा रहे थे। इससे इस संगठन के मंसूबे जाहिर होते हैं। लखनऊ व आसपास के जिलों में सक्रिय पीएफआइ व सीएफआइ के कई सक्रिय सदस्य एक बार फिर पुलिस व खुफिया एजेंसियों के निशाने पर आ गए हैं। एसटीएफ अब उन युवकों के बारे में जानकारी कर रही है, जिन्हें विस्फोट दिया गया था।

बता दें कि पीएफआइ के कमांडर केरल निवासी अन्सद बदरुद्दीन और फिरोज खान को मंगलवार शाम कुकरैल तिराहे के पास से स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस, पिस्टल, कारतूस बरामद किया गया है। दोनों से पूछताछ में सामने आया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में एक-साथ आतंकी हमले की साजिश थी। दोनों आरोपित सूबे में वसंत पंचमी के मौके पर धमाकों की योजना में शामिल थे। फिरोज युवकों को हथियार चलाने व बम बनाने की ट्रेनिंग देता था। उनके पास से हिंदूवादी संगठनों के प्रमुख व बड़े नेताओं की सूची भी मिली है। कई दस्तोवज मलयालम भाषा में हैं। दोनों लखनऊ आने के बाद कुछ युवकों को विस्फोटक बांट भी चुके थे। दोनों आरोपितों के विरुद्ध थाना एसटीएफ, लखनऊ में एफआइआर दर्ज की गई है।

एक नजर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेताया, महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन

मुंबई । महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चिंता व्यक्त करते हुए मंगलवार को जिला वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राजस्व आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा जो लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहें हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा, यह तय करना लोगों पर निर्भर है कि वे लॉकडाउन वापस चाहते हैं या कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर लोग मास्क नहीं पहनते हैं या स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जिला और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें।

लोग बड़े पैमाने पर पार्टियों और समारोहों में भाग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कलेक्टरों से कहा कि यदि वे सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और मास्क पहनने का पालन नहीं करते हैं, तो वे रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस को रद भी किया जा सकता है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में बीते रविवार को पिछले एक माह से अधिक समय में सबसे ज्यादा कोरोना के 4092 नए मामले सामने आए वहीं मंगलवार को 3663 नए मामले दर्ज किए गए। बीते सात दिनों से प्रतिदिन 3,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। मुंबई से 461 केस आए, मुख्यमंत्री ठाकरेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह फैसला नागरिकों को स्वयं करना होगा कि क्या वे संक्रमण पर नियंत्रण के लिए फिर से लॉकडाउन का सामना करना चाहते हैं उन्होंने कहा, ''राज्य के लोगों को इसका फैसला करना है कि वे लॉकडाउन चाहते हैं या कुछ पाबंदी के साथ मुक्त रहना चाहते हैं। मेरी लोगों से अपील है कि मास्क पहनें और भीड़-भाड़ से बचने का प्रयास करें अन्यथा फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है।

महिष्मति गौ सेवा रक्तदान संगठन ने डिंडोरी पहुंचकर बचाई जान

मण्डला। नर्मदा स्वास्थ्य सेवा व लोक-सेवा समिति, अमलाई के विनम्र अनुरोध पर माहिष्मती गौ सेवा रक्तदान संगठन- के माध्यम से जिला डिंडोरी में ओ नेगेटिव ब्लड की पूर्ति, दो यूनिट की गयी। जिला अस्पताल में भर्ती फूलचंद मरावी को ओ नेगेटिव ब्लड की बहुत जयादा, अति आवश्यकता थी। जो कि डिंडोरी जिला में उपलब्ध नहीं होने के कारण, मंडला जिला के मोती नाला एवं अंजनिया से डोनर लाकर डिंडोरी में रक्तदान करवाया गया। रक्तदान डोनर प्रथम नामदेव मोतीनाला से एवं देवा पटेल अंजनिया से, आप दोनों ने रक्तदान किया। नेहरू स्मारक जिला कांग्रेस कर्यालय से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में शहीद हुये किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मोमबत्ती जलाकर शहीद हुए किसानो को याद किया, वहीं श्राद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष एडव्होकेट राकेश तिवारी, अखिलेश कछवाहा, महिला कांग्रेस से शंकुन जंघेला, दीपक बैरागी, आशू जैन एवं वरिष्ठ कांग्रेसी राजेन्द्र राजपूत एवं अनेक कांग्रेसी उपस्थित थे।

प्लास्टिक विहीन नर्मदा जयंती हो

मंडला। जनसुनवाई में सरिता अग्निहोत्री द्वारा पुनः प्लास्टिक एवं अमानत पनियों के प्रतिबंध पर आवेदन दिया। ज्ञात हो श्रीमती सरिता अग्निहोत्री कई दशक से प्लास्टिक के विरोध में काम कर रही है साथ ही कई विकल्प प्लास्टिक के रूप में प्रचार और प्रसारित कर चुकी हैं। जनसुनवाई में श्रीमती सरिता अग्निहोत्री के द्वारा जो आवेदन दिया उसमें प्लास्टिक के दिए जो कि नर्मदा के घाट में नर्मदा के जल में ही छोड़े जाते है। साथ ही नर्मदा जयंती के समय में प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास पानी पाउच, डिस्पोजल प्लेट का उपयोग कर मां नर्मदा के तट को गंदा करते हैं साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित होता है इस के लिये लोग जागरूक हो मां नर्मदा का तट आपके घर का मंदिर है इसे गंदा ना करें आपने आगे बताया कि लोग कचरा जिसमें की प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा रहती है उसको जला देते हैं इससे विषैली गैस निकलती हैं और विषैला लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है इस के लिये हर व्यक्ति की जवाबदारी है कि वह अपने घर से निकलने वाले कचरे को स्वयं देखें और पृथक्करण का कार्य वह खुद करें क्योंकि प्लास्टिक पॉलिथीन को एकत्र करके वह नगर पालिका ग्राम पंचायतों को देवें यह कारखानों में ऊर्जा के रूप में काम आ रहा है प्लास्टिक की पन्नी में खाने का सामान सब्जी भाजी साथ ही कांच लोहे का सामान यह सब आम जनता के द्वारा फेंका जाता है तो भूख जानवरों को इसका पता नहीं होता और वे उसे समूचा निकल जाते हैं उनके पेट में यह सब पहुंच कर उनके लिए जानलेवा बन जाता है उस जानवर की मौत के जवाबदार भी हम ही हैं। हमें जागरूक होना होगा और जिस तरह से हम अपने घर को साफरखते हैं उस तरह से अपने परिवेश को भी साफ रखना होगा।

कमिश्नर ने ली वीडियो कॉन्फ्रेसिंग बैठक

मण्डला। जबलपुर संभाग आयुक्त चंद्रशेखर बोरकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जबलपुर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिलेवार बारिश की स्थिति के बारे में विस्तार से जाना। उन्होंने बारिश से फसल नुकसान तथा जनजीवन की क्षति के बारे में रिपोर्ट मांगी। श्री बोरकर ने कहा कि बारिश के कारण फसलों एवं जनमानस की किसी भी प्रकार की क्षति को तत्काल संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों को नियमित रूप से निराकृत कर संभाग की स्थिति को और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों की कलेक्टर अपने स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा करें। संभाग आयुक्त ने संभाग के सभी जिलों में चल रहे कोविड टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कोविड टीकाकरण की आंकड़ेवार समीक्षा करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बोरकर ने धान उपार्जन के भुगतान, रबी उपार्जन की तैयारी तथा पंजीयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जाना। उन्होंने रबी पंजीयन के लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने की बात कही। कमिश्नर ने बैठक में मिलावट से मुक्ति अभियान के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मिलावट के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहे तथा दोषियों के विरूद्ध मामले पंजीबद्ध करें। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित रूप से सेम्पल लेने के निर्देश दिए। श्री बोरकर ने राशन वितरण में कालाबाजारी करने वाले तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम

मण्डला। केन्द्रीय इस्पात राजयमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का 17 फरवरी को मंडला आगमन हो रहा है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री कुलस्ते 17 फरवरी को प्रातः 9:30 बजे जबलपुर से मंडला के लिए रवाना होंगे एवं मंडला पहुंचकर दिशा की बैठक में भाग लेंगे। श्री कुलस्ते दोपहर 1 बजे रानी अवंती बाई उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे पर्यटन विकास की समीक्षा बैठक एवं स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री रात्रि 8 बजे मंडला से जेवरा के लिए रवाना होंगे एवं जेवरा में रात्रि विश्राम करेंगे। 18 फरवरी को प्रातः 11 बजे जेवरा से प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे विकासखंड नैनपुर के अंतर्गत पाठासिहोरा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बने उच्च स्तरीय पुल पाठासिहोरा से कुरला तक का लोकार्पण करेंगे। श्री कुलस्ते शाम 4 बजे पाठासिहोरा से झुलपुर पहुंचकर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके पश्चात मंडला के लिए रवाना होकर शाम 7 बजे स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्यमंत्री श्री कुलस्ते मंडला से रात्रि 8 बजे जेवरा के लिए रवाना होंगे एवं रात्रि विश्राम करेंगे। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री 19 फरवरी को जेवरा में छात्रावास का लोकार्पण करेंगे एवं दोपहर 1 बजे जेवरा से विकासखंड मेहंदवानी के पगनिया पहुंचेंगे।

किसानों की राय, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भविष्य के लिए निश्चिंत होंगे

जयपुर । कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का राजस्थान में कोई खास असर नजर नहीं आता। इसी बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (अनुबंध खेती) को लेकर एक तरफ जहां आंदोलन कर रहे किसान संगठन कई तरह की आशंकाए जता रहे हैं, वहीं राजस्थान में अधिक खेती वाले बीकानेर, झुंझुनूं व नागौर जिलों के किसानों का मानना है कि इससे किसानों को अपनी फसल का तयशुदा मूल्य मिल जाता है। इससे अगली फसल के लिए धन जुटाने की समस्या नहीं रहती और जीवनयापन भी सुगम हो जाता है।

हालांकि, आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का मानना है कि अनुबंध के तहत खेती करने से किसान को अपनी फसल का बाजार के हिसाब से दाम नहीं मिल पाएगा और जो भी फायदा होगा वह अनुबंधकर्ता के हिस्से में चला जाएगा। अजमेर जिले के किशनगढ़ निवासी किसान रामचंद्र गुर्जर का कहना है कि वर्तमान समय में खेती करना घाटन व जोखिम का काम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान चाहता है कि उसे अपनी फसल का न केवल उचित मूल्य मिले, बल्कि पर्याप्त फायदा भी मिले।

गुर्जर ने कहा कि कई बार मौसम की मार के कारण तो कई बार अन्य कारणों से फसल खराब हो जाती है। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता। किसान कर्ज लेकर खेती करता है, लेकिन कई बार फसल खराब होने से वह परेशान हो जाता है। पिछले कुछ सालों में कोटा संभाग में किसानों की आत्महत्याओं के कई मामले सामने आए थे। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई किसान की आने वाली फसल का पहले ही एक तय कीमत पर अनुबंध कर ले तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

बीकानेर जिले के देशनोक निवासी हनुमान सिंह ने कहा कि अनुबंध पर खेती से किसान कुछ हद तक भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाएगा। ज्यादा जोखिम नहीं उठाने वाले किसान अपनी जमीन को एक निश्चित मूल्य पर किसी अन्य को अनुबंध पर देकर निश्चिंत हो सकता है। वर्तमान में बीकानेर जिले में कई किसान अनुबंध पर खेती कर रहे हैं। दौसा जिले के आलूदा गांव निवासी मुकेश कुमार शर्मा का कहना है कि अनुबंध पर खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि इससे उन्हे अपनी उपज के लिए परेशानी मुक्त उत्पादन मिलेगा।

शर्मा के 10 बीघा का खेत है। उनका कहना है कि अनुबंध खेती से फसल की बिक्री को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही फसल खराब होने पर बीमा का लाभ भी मिल सकेगा। कीमतों में उतार-चढ़ाव के खतरे से किसान सुरक्षित होगा। जयपुर जिले के चौमू निवासी रामलाल जाट का कहना है कि अनुबंध खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे वे अपनी उपज को अच्छी कीमत पर देश में कहीं भी बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की समस्या भी खत्म होगी। मूल्य पहले से तय होने के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव के जोखिम से मुक्ति मिलेगी।

कुछ बोले नुकसान होगा

हनुमानगढ़ जिले के नोहर निवासी श्रवण तंवर का कहना है कि अनुबंध खेती के तहत किसानों को अल्पकालिक लाभ होगा, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान होगा। अनुबंधकर्ता पर निर्भरता रहेगी। किसान मोल-भाव नहीं कर सकेगा। नागौर निवासी राजेंद्र सैन ने कहा कि किसान मोल-भाव नहीं कर सकेगा। विवाद होने पर किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकेगा, यह सबसे बड़ी मुश्किल होगी।

दूसरी बार अपना वादा पूरा नहीं कर सके राजस्थान कांग्रेस के अजय माकन

जयपुर । राजस्थान के कांग्रेसियों से पार्टी महासचिव अजय माकन द्वारा किया गया वादा एक बार फिर पूरा नहीं हो सका। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि प्रदेश के नेताओं व कार्यकर्ताओं से किए गए वादे पर माकन नहीं उतरे। माकन ने इस माह की शुरूआत में कहा था कि 15 फरवरी तक जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियों का काम पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओ को जिला स्तर की विभिन्न कमेटियों में नियुक्तियां दी जाएगी। लेकिन तय समय सीमा निकलने के बाद कांग्रेसियों में खलबली मचने लगी है।

कांग्रेसियों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या माकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बिना चर्चा किए वादा करते हैं, जो पूरा नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री फिलहाल किसी भी तरह की राजनीतिक नियुक्ति करने के मूड में नहीं है। इससे पहले माकन ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि 31 जनवरी तक राज्य स्तरीय निगम व बोर्डों में वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति करने के साथ ही जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी।

उन्होंने कहा था कि हर हाल में राजनीतिक नियुक्तियों का काम 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की बात भी कही थी। लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा के बजट सत्र और अगले माह में संभावित चार विधानसभा सीटों के उप चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां करने के मूड में नहीं है।

माकन लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बना रहे है लेकिन वे नहीं मान रहे। माकन की दुविधा यह है कि एक तो सचिन पायलट की बगावत को थामने के लिए उनसे किए गए वादे के अनुरूप मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां कराना, वहीं गहलोत मानने को तैयार नहीं है।

गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतक नियुक्तियां अपने हिसाब से करना चाहते हैं। सत्ता व संगठन सूत्रों के अनुसार गहलोत अप्रैल से पहले किसी भी तरह का निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि करीब 40 हजार राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। जिला स्तर की नियुक्तियों के नाम उनके पास आ चुके,विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएगी।

टूलकिट मामले की आरोपी निकिता जैकब को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक

मुंबई, एजेंसी । बॉम्बे हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो उसे 25 हजार के मुचलके पर राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि जस्टिस नाइक की बेंच ने औरंगाबाद बेंच के निर्णय का भी जिक्र किया था उसके बाद निकिता को राहत दी गई। दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया था।

कोर्ट में निकिता जैकब की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने बताया था कि टूलकिट कई लोगों द्वारा किसानों के आंदोलन को समर्थन के लिए तैयार किया गया था। इसमें न तो लाल किले पर हुए प्रदर्शन का उल्लेख है और न ही किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन इन सबके बावजूद भी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से हाइकोर्ट में वकील हितेन वेनेगांवकर ने पैरवी की थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दिशा ने जैकब और शांतनु मुलुक के साथ मिलकर टूलकिट बनाया और इसे अन्य लोगों के साथ साझा कर देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। गौरतलब है कि इस मामले के एक अन्य आरोपी शांतनु ने भी हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। औरंगाबाद पीठ की जस्टिस विभा कांकनवाडी ने इस पर सुनवाई करते हुए शांतनु को दस दिन तक गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी।

महाराष्ट्र के जलगांव में एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रकोप, 65 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत

मुंबई । महाराष्ट्र के जलगांव में 15 फरवरी को 65 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हो गई। सरकार के अनुसार संक्रमित क्षेत्र से अब तक 7,12,172 पोल्ट्री पक्षी (नंदुरबार जिले के 5,78,360 पक्षी सहित), 26,03,728 अंडे और 72,974 किलोग्राम मुर्गी चारा नष्ट हो चुका है। केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, 30 जनवरी तक 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों- केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के पोल्ट्री पक्षियों में एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप की पुष्टि हो गई है।

इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और बिहार सहित 13 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने कौवा / प्रवासी / जंगली पक्षियों के बीच एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हो चुकी है।

महाराष्ट्र में बीते शुक्रवार को भी 151 पक्षियों की बर्ड फ्लू के कारण मौत हो गई थी। इनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए थे। मारे गए पक्षी बुलढाणा, अमरावती के हैं इनमें जलगांव से 134 कुक्कुट भी शामिल हैं। पुणे स्थित रोग जांच केंद्र में इनके सैंपल की जांच हो रही है।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के साथ ही पूरे देश में बर्ड फ्लू का खतरा बना हुआ है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के नंदुरबार के नवापुर में 12 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की वजह से कई पक्षियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद लगभग 1 लाख पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया था।

जेल में बंद आसाराम की बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द के बाद सीसीयू में किया गया रेफर

जयपुर । अपने ही गुरुकुल की छात्रा के साथ यौन दुराचार के मामले में जीवन की अंतिम सांस तक कारावास की सजा पाने वाले आसाराम की तबीयत मंगलवार मध्यरात्रि को बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के सीसीयू में भर्ती के लिए रेफर किया है। आसाराम को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।

मंगलवार मध्यरात्रि के बाद जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ी जिसके बाद पहले उन्हें जेल के डिस्पेंसरी में चेक किया गया और उसके बाद स्थिति बिगड़ने के अंदेशे को लेकर जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। हालांकि जेल एंबुलेंस से उतरने के बाद आसाराम स्वयं चलकर गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे थे।

मीडिया के पूछने पर उन्होंने सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द होने की बात कही। जांच के समय ले जाते हुए वह चालानी गार्ड और वहां मौजूद पुलिस से भी बतियाते देखे गए।

इस दौरान पुलिस के माकूल बंदोबस्त रहे। एमजीएच में आसाराम का एक्सरे लिया गया उसके अलावा उनका ब्लड टेस्ट भी किया गया है। मेडिकल जांच के बाद आसाराम को डॉक्टरों ने मथुरादास माथुर अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती होने के लिए रेफर किया जिसके बाद पुलिस जाब्ता उन्हें जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल लेकर गया।

आसाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल लाने की सूचना जैसे ही बाहर पहुंची वैसे ही बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु रात को ही जोधपुर के गांधी अस्पताल पहुंच गए। जिसके बाद एक बार की अफरा-तफरी जैसा माहौल देखने को मिला जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला और सुरक्षा के बीच आसाराम को गांधी हॉस्पिटल से एमडीएम अस्पताल पहुंचाया गया।

बताओ कितने हैं पुराने पेड़ , कितने कटेंगे और कितने बचेंगे ...

डुमना रोड मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने डुमना में रोड चौड़ीकरण व अन्य विकास कार्यो को लेकर हरे-भरे जंगल को काटे जाने को चुनौती देने वाले मामले को काफी सख्ती से लिया। चीफ जस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने मामले में सरकार को निर्देशित किया है वह पूरे मामले में सेर्व कराकर एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश करे कि कितने पुराने पेड़ है और कितने पेड़ कटेंगे और कितने नए झाड़ लगाए जाएंगे तो उसमें से कितने बचते है। युगलपीठ ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को निर्धारित की है।यह जनहित का मामला गढ़ा गंगा नगर कालोनी निवासी निकिता खम्परिया की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया कि डुमना के हरे-भरे जंगल को बिना केन्द्र सरकार की अनुमति लिये काटा जा रहा है, जो कि अवैधानिक है। आवेदक का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण व अन्य विकास कार्यो के नाम पर शहरी जंगल को काटा जा रहा है, जबकि नियमानुसार उसकी केन्द्र सरकार से नहीं ली गई है। इतना ही नहीं आवेदक का कहना है कि नगर निगम की जिस अनुमति को दर्शाया जा रहा है, वह उक्त मामले में पर्याप्त नहीं है। मामले में केन्द्र सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, प्रमुख सचिव वन विभाग, नगर निगम आयुक्त व पीडब्ल्यूडी ईई को पक्षकार बनाया गया है। मामले में न्यायालय ने 29 सितंबर को अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये थे। मामले की पूर्व सुनवाई पर सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि वह हरे-भरे पेड़ों को नहीं काटेंगे, बल्कि उन्हें संरक्षित करेंगे। मामले में मंगलवार को आगे हुई सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रेयश पंडित पैरवी कर रहे है।

ब्रिटिश फोर्ट के छात्र तन्मय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित

जबलपुर। (एजेंसी)। संस्कारधानी के लिए ये गर्व की बात है कि शहर के ही एक छात्र ने लगातार अपने द्वारा निर्देशित कई फिल्में फिल्म फेस्टिवल में प्रसारित हो रही हैं। ब्रिटिश फोर्ट फाउण्डेशन के विद्यार्थी तन्मय श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित शार्ट डाक्यूमेंट्री फिल्मों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया है। उपरोक्त जानकारी ब्रिटिश फोर्ट फांडेशन संचालक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक व लेखक अनुराग सोनी ने मंगलवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में दी।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान छात्र तन्मय श्रीवास्तव ने बताया कि उनके द्वारा निर्देशित फिल्म द स्टोरी ऑफ क्लोद्स, ब्रेथ ऑफ लाईफ, ब्लैक वॉटर, द रेसिडेंसी, द रॉयल टेस्ट, पिक्चर ऑफ हिस्ट्री, द व्हाइट मुगल, द बंद, डीड यू नो लैक्सीज, वॉइसीज ऑफ द डेड, नाईनटी डेज टू लीव, द लास्ट पैराडाइज, द बिलीयन डॉलर स्पाई, रिवाइवल एवं कुछ अन्य फिल्में अब तक फिल्म फेस्टिवल में प्रसारित हो चुकी हैं। तन्मय ने बताया कि स्कूल के डायरेक्टर अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक एवं लेखक अनुराग सोनी भी उनहें समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहे हैं और उन्हें स्कूल का प्रोत्साहन मिलता रहा है। उनकी फिल्में सैन-डियेगो, यूथ फिल्म फेस्टिवल, म्युनिक फिल्म फेस्टिवल, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल, ऑस्टीन फिल्म फेस्टिवल, लंदन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एवं इस्तांबुल फिल्म फेस्टिवल में प्रसारित हो चुकी है। तन्मय श्रीवास्तव द नेशनल यूथ फिल्म एकेडमी ऑफ ब्रिटेन में क्रू मेम्बर के रूप में विभिनन प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट पर कार्य कर चुके हैं।

बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज बोले- हिन्दुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं, हिन्दू जैसा दोस्त नहीं

उदयपुर । सुभाष शर्मा। भाजपा में अल्पसंख्यक नेता एवं बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज का कहना है कि हिन्दुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है और ना ही हिन्दू जैसा कोई दोस्त। पार्टी उनकी मां के समान है और वह देश के मुसलमानों को सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। शाहनवाज देर शाम उदयपुर आए थे और इस बीच फतहसागर किनारे बने रोटरी भवन में उनसे बातचीत का अवसर मिला।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विश्व के सबसे अधिक अधिकार, मौके तथा आजादी यदि मुसलमानों को है तो वह हिन्दुस्तान में है। भाजपा उनके हितों की रक्षा करती आई है। हमने मुसलमानों को मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि नागरिक के तौर पर देखा है।

कांग्रेस तो विपक्ष कहलाने लायक भी नहीं- शाहनवाज ने कहा कि कांग्रेस जिसने देश पर छह दशकों तक शासन किया, वह अब विपक्ष तक कहलाने तक लायक नहीं। विपक्ष की भूमिका क्या होती है, यह भी उन्हें सीखने की जरूरत है। विरोध के नाम पर इनके नेता राष्ट्रद्रोहियों की पैरवी में लग जाते हैं।

किसानों को केवल बरगलाया जा रहा है

शाहनवाज से किसान और कृषि बिल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व दुनिया में नहीं। किसानों के हित में बिल लाए गए, इसके बावजूद उन्होंने बड़े दिल के साथ किसान बिल को डेढ़ साल तक स्थगित करने की बात कही थी लेकिन कांग्रेस किसानों को बरगलाने में जुटी है।

शाहनवाज ने कहा कि भाजपा जो काम उन्हें सौंपती है, वह उसे पूरी शिद्दत से करते हैं। कश्मीर में कमल खिलाने भेजा तो उसमें सफलता हासिल की। हर मुश्किल काम उन्हें दिया गया और सफलता से उसे पूरा किया। अब बिहार सरकार के साथ काम का अवसर दिया है। इससे पहले सबसे कम उम्र में केन्द्रीय मंत्री बनने का रिकार्ड भी उनके नाम है।

भाजपा में निर्णय पार्टी करती है, व्यक्तिगत नहीं- शाहनवाज का कहना था कि भाजपा में व्यक्ति की नहीं, बल्कि पार्टी की चलती है। यहां संगठन तय करता है कि किसे कौन सा काम देना है। पार्टी को उन्होंने मां का दर्जा देते हुए कहा कि जो भी काम उन्हें सौंपा जाएगा, वह पूरी शिद्दत से पूरा करेंगे।

पेट्रोल-डीजल महंगे हैं लेकिन घटेंगे भी

शाहनवाज हुसैन ने माना कि इन दिनों पेट्रोल-डीजल महंगे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि आज महंगे तो कल सस्ते भी होंगे। यह बाजार पर निर्भर है। इसी तरह रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर उन्होंने अपने विचार जताए।

फ्रंटलाइन वर्कर के लिए पंजीयन कराने का आज आखिरी दिन

जबलपुर। कोरोना वेक्सीन लगवाने से छूट गये फ्रंटलाइन वर्कर्स 17 फरवरी तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ एसएस दाहिया के अनुसार राज्य शासन द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे राजस्व, पुलिस, नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के पंजीयन की तिथि 17 फरवरी तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि फ्रंटलाइन विभागों के जिला प्रमुखों को टीका लगवाने से शेष रह गये अधिकारियों.कर्मचारियों की सूची इसके लिए निर्धारित प्रारुप में देनी होगी। जिला टीकारण अधिकारी ने बताया कि 17 फरवरी तक पंजीयन कराने वाले तथा शेष रह गये फ्रंट लाईन वर्कर्स को कोरोना के टीके लगाने 19 फरवरी को मापअप राउंड आयोजित किया जायेगा।

Bigg Boss 14

देवोलीना भट्टाचार्जी

ने बाहर आते ही फैंस को दिया मैसेज, बोलीं- मुझे अपने असली इमोशन्स के लिए...

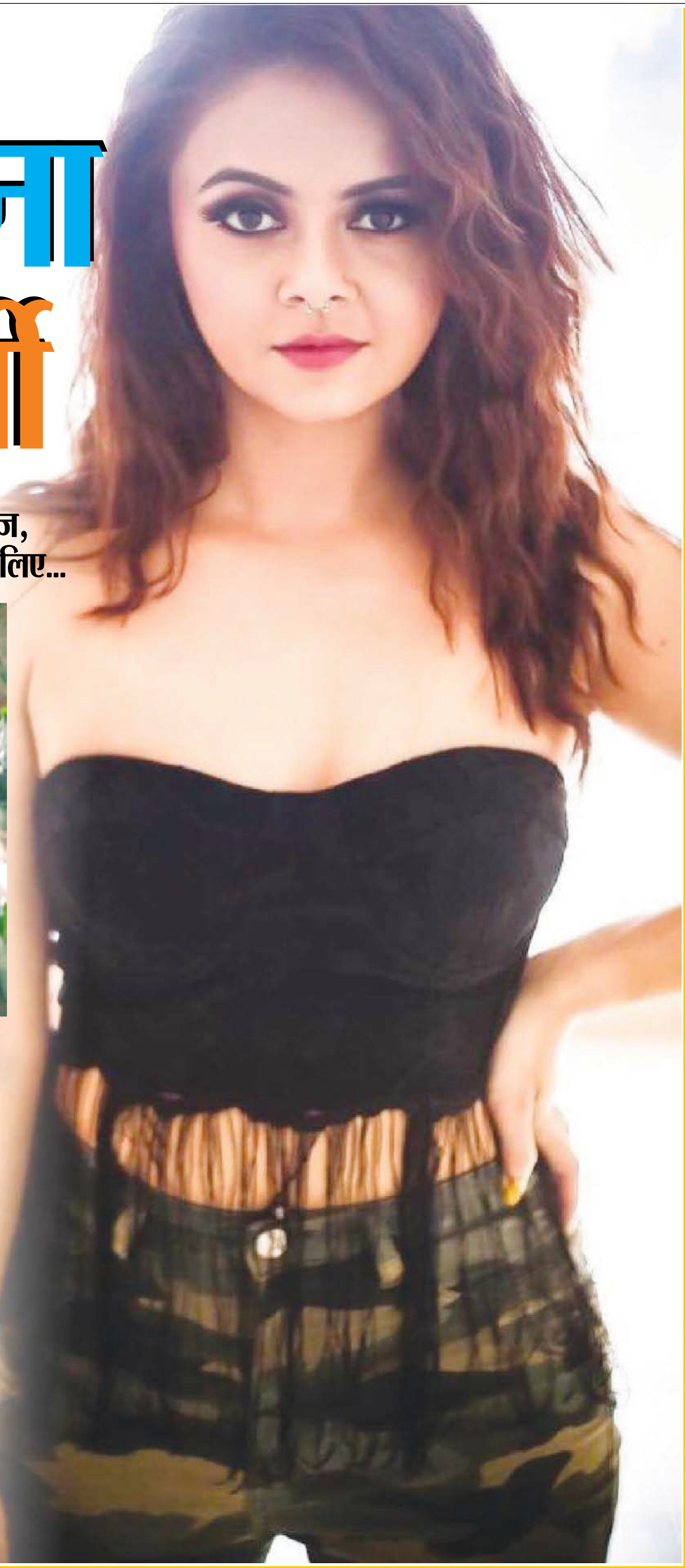

टीवी के विवादित शो बिग बॉस 14 (**Bigg Boss** 14) में देवोलीना भट्टाचार्जी का सफर समाप्त हो गया है. वह बिग बॉस के घर से बाहर हो गई हैं. उन्होंने एजाज खान के प्रॉक्सी के तौर पर घर में एंट्री ली थी. दरअसल, एजाज को किसी काम को लेकर कमिटमेंट के चलते शो से बाहर होना पड़ा था. अब एजाज के घर से बाहर होने पर देवोलीना को भी शो से रुखसत होना पड़ा है. घर से बाहर होने के बाद देवोलीना ने फैंस के साथ बात की है. उन्होंने फैंस के नाम पहला संदेश जारी किया है. उन्होंने कहा, फैंस मेरे लिए प्रायोरिटी हैं.

देवोलीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से बिग बॉस 14 का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वह सलमान खान के सामने अपनी भावनाओं को लेकर बात कर रही हैं. वीडियो शेयर करते हुए देवोलीना ने लिखा, अगर आपकी भावनाएं असली हैं तो आपको इसके किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है. मेरे लिए मेरी जिंदगी में शामिल हर इंसान मेरी प्राथमिकता में हैं. फिर वो मेरी एंजल (डॉगी) हो, मेरी मां, भाई या मेरे फैंस हों. हालांकि एंजल मेरी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर हैं.

वह इस समय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उन्होंने घर में उनके सपोर्टर के तौर पर आए पारस छाबड़ा को गिरगिट कहा है. देवोलीना ने अपने ट्वीट में लिखा, उसको सपोर्टर का मतबल समझना चाहिए. सपोर्टर के नाम पे काला दाग बन गया. गिरगिट. सपोर्ट करना नहीं था तो आना ही नहीं चाहिए था. गंदी गंदी हरकतें करेगा तो तारीफ थोड़ी बटोरेगा. बता दें कि एक टास्क के दौरान पारस ने देवोलीना को सपोर्ट करने से मना किया था.

टीवी शो %साथ निभाना साथिया की एक्ट्रेस देवोलीना भटाचार्जी ने बिग बॉस में अपनी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए थे. उन्होंने बताया था कि जब वह 12 साल की थी, तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. वह तीन भाई-बहन थे, जिनमें से सबसे छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है. वह बिग बॉस के घर में राखी से ज्यादा करीब थीं. राखी सावंत और देवोलीना भट्टाचार्जी अच्छे दोस्त बन गए हैं.

आलिया भट्ट

शाहरुख खान एक बार फिर होंगे साथ, फिल्म डार्लिंग्स में करेंगे काम

डियर ज़िन्दगी (Dear Zindagi)' के बाद शाहरुख खान और आलिया भट्ट इस बार डार्लिंग्स के साथ एक मजेदार मां-बेटी की कहानी बताने के लिए एक साथ आ गए हैं. लेकिन, शाहरुख खान इस बार एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि निर्माता का पदभार संभाल रहे हैं. शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने पहली बार गौरी शिंदे की डियर जिंदगी में साथ काम किया था, जो सफल साबित हुई थी. अब, शाहरुख खान बतौर निर्माता, डार्लिंग्समें आलिया भट्ट के साथ काम करने वाले हैं. सूत्रों के अनुसार, यह फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा विकसित की गई है.कुछ समय पहले आलिया को डार्लिंग्स की स्टोरी सुनाई गई थी. एक सूत्र ने बताया, उन्हें यह बेहद पसंद आई और तुरंत फिल्म के लिए हामी भर दी. डार्लिंग्स के साथ जसमीत के रेने बतौर निर्देशक डेब्यू कर रही हैं, जिन्होंने कई फिल्मों पर एसोसिएट डायरेक्टर और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है और पहले फोर्स 2, फन्ने खान और पति पत्नी और वो जैसी फिल्में लिखी हैं. फिल्म में आलिया की मुख्य भूमिका के साथ-साथ शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू जैसे कलाकार हैं.

कहा जा रहा है कि यह एक प्यारी मां-बेटी की जोड़ी, जो आलिया और शेफाली द्वारा निभाई गई है, के बारे में एक विचित्र कहानी है, जो ज़िंदगी में पागलपन से भरपूर परिस्थितियों से गुजरती हैं. सूत्र ने कहा, "यह फिल्म मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार के बैकड्रॉप पर स्थापित है और दो महिलाओं के जीवन को दर्शाया गया है, जहां उन्हें असाधारण परिस्थितियों में साहस और प्यार मिल जाता हैं.इस सप्ताह फिल्म की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है और स्रोत के अनुसार, डार्लिंग्स की शूटिंग 2021 के पहले तिमाही में शुरू की जाएगी.

बल्कि फिल्म को इस साल ही रिलीज करनी की तैयारी है. प्री-प्रोडक्शन का काम जोरों पर चल रहा है और टीम मुंबई में बहुत जल्द शूटिंग शुरू करने की तैयारी में है.डार्लिंग्स के अलावा, शाहरुख खान प्रोडक्शन की टीम प्रोडक्शन फ्रंट पर कई फिल्मों पर काम कर रही है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा अभिनीत लव हॉस्टल जो फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है और अभिषेक बच्चन के साथ बॉब बिस्वास पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन ने सेलिब्रेट किया बेटी आराध्या बच्चन संग वैलेंटाइन्स डे, सेल्फी, केक और गुलाब संग फोटोज वायरल

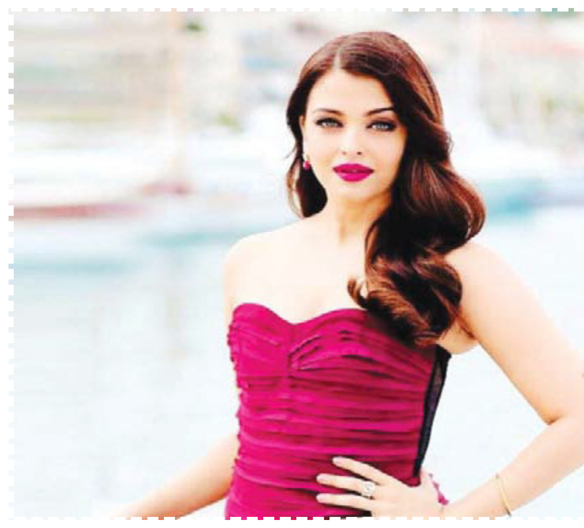

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने दर्शकों के दिलो में अपने काम से जगह बनाई। एक के बाद एक हिट फिल्में देकर उनका विश्वास जीता। अब ऐश्वर्या राय बच्चन एक बेटी की मां हैं, जिसका नाम आराध्या बच्चन है। हाल ही में वैलेंटाइन्स डे के मौके पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने कुछ फोटोज शेयर कीं। इसमें बेटी संग सेल्फी से लेकर गुलाब और केक की फोटोज शामिल हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन ने बेटी संग कैमरे में पोज देती नजर आ रही हैं। फोटोज में ऐश्वर्या बहुत कम मेकअप में नजर आ रही हैं। वहीं, आराध्या बच्चन हाथ में लाल रंग का हार्ट पकड़े नजर आ रही हैं। फोटोज शेयर करते हुए ऐश्वर्या ने लिखा, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूं, जिसकी कोई सीमा नहीं, मेरी डार्लिंग एंजल आराध्या।

फैन्स ऐश्वर्या राय बच्चन की पोस्ट और फोटोज पर कॉमेंट्स कर रहे हैं और हार्ट इमोजी बना रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले ऐश्वर्या राय ने 2007 में आई अपनी हिट फिल्म गुरु के प्रीमियर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। ब्यूटी गर्ल इन तस्वीरों में नीली साड़ी में नजर आ रही हैं और अभिषेक बच्चन की तरफ देख रही हैं। वहीं अभिषेक बच्चन मीडिया से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में फिल्म के डायरेक्टर मणि रत्नम भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए ऐश्वर्या राय ने कैप्शन में लिखा है, इसी दिन...14 साल... गुरु हमेशा। ऐश्वर्या राय की इन तस्वीरों पर फैन्स ने कॉमेंट करते हुए कहा कि वह उन्हें जल्दी ही एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें एक बार फिर से मणि रत्नम की किसी फिल्म में आना चाहिए। अभिषेक बच्चन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, एक फिल्म के लिए मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था। इसी दौरान एक दिन मैं होटल की बालकनी में खड़ा सोच रहा था कि वह दिन कितना अच्छा होगा, जब हम शादी कर लेंगे और साथ होंगे। कुछ सालों के बाद हम वहां गुरु मूवी के प्रीमियर के लिए पहुंचे थे। फिल्म के प्रीमियर के बाद हम होटल में वापस लौट आए थे। फिर मैं ऐश्वर्या को उसी बालकनी में लेकर गया और उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया।

शिल्पा शेट्टी के पति ने सबके सामने खोले बेडरूम सीक्रेट, राज कुंद्रा की बात सुनकर चौंक गई एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई दे जाती हैं। हाल ही में शिल्पा एक बार फिर कुछ ऐसे ही कारणों से सुर्खियों में आ गई हैं। उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा के साथ एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दोनों एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच राज सबके सामने %बेडरूम सीक्रेट% शेयर कर देते हैं, वहीं शिल्पा ये सुनकर शिल्पा चौंक जाती हैं और शर्म से लाल हो जाती हैं।

दरअसल, शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उनके एक कॉन्टेस्ट के तहत लिया गया है। वैलेंटाइन डे के मौके पर इस पावर कपल ने यॉर ड्रीम स्टोरी शेयर करने का एक कॉन्टेस्ट रखा था। वीडियो में राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी से पूछते कि तुम्हारा फेवरेट जॉनर कौन सा है. इस पर शिल्पा शेट्टी कुछ नहीं कहतीं हैं तो राज शरारती अंदाजा लगाते हुए खुद ही बोल पड़ते हैं- फिफ्टी शेड्स ऑप ग्रेझ्र.. ये सुनते ही शिल्पा शेट्टी शर्म से लाल हो जाती हैं और जोरों से हंसने लगती हैं। वीडियो में दिख रहा है कि राज भी बाद में हंसते हुए कहते हैं- सॉरी यह हमारा बेडरूम सीक्रेट है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए शिल्पा अपने फैंस को पार्टनर के लिए एक नसीहत देते हुए लिखती हैं- किसी ऐसे को ढूंढो जो आपको पागल बनाए और उसी वक्त आपको हंसाए भी... इसके जैसा%। वहीं शिल्पा के इस वीडियो को ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। हर कोई इन दोनों की कैमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहा है।

हार से लें वापसी की सीख : रुट

चेन्नई, (एजेंसी)। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट ने कहा है कि दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में मिली हार से हमें सबक सीखना चाहिये। रुट ने कहा कि हमें भारतीय टीम से सीखना होगा कि किस प्रकार पिछड़ने के बाद वापसी की जाती है। रूट ने कहा कि हमारे लिए यह किसी शिक्षा की तरह था। हमें जल्दी से सीखना होगा क्योंकि कई बार आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है। रूट हालांकि यह मानने को तैयार नहीं हैं कि इंग्लैंड की टीम अब श्रृंखला में वापसी नहीं कर पाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई की टीम अपने पिछले प्रदर्शनों से सबक लेगी। जैसा कि मैंने पिछले मैच के बाद कहा था कि यह जरूरी है कि हमारे कदम जमीन पर ही रहें। ऐसे में जब हम जीतते हैं तो हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती। वहीं इसी प्रकार जब हारते है तो हमें ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। रूट ने कहा कि हमने पहले भी काफी कठिन हालातों में अच्छा प्रदर्शन किया है हालांकि यह सही है कि इस मैच में हम तीनों ही क्षेत्रों में पिछड़े हैं। हम यह देखेंगे कि उन्होंने स्पिनरों की मददगार पिच चीजों को कैसा किया। यहां हमने जितना सोचा था गेंद को उससे ज्यादा

उछाल मिल रही थी। हम हालांकि इसे सीखने के नजरिए देखेंगे और यह तय करेंगे कि अगली बार बेहतर प्रदर्शन करें।

चेपॉक मैदान की इस पिच को लेकर रूट ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण विकेट था। टॉस जीतना जरूरी था लेकिन वह भी जीत की गारंटी नहीं देता। वहीं भारतीय टीम ने यह दिखाया कि इस पिच पर रन बनाए जा सकते हैं और उससे निपटने का तरीका निकाला जा सकता है। हमें भारत से सीखने की जरूरत है। रूट ने कहा कि उनके गेंदबाजों को बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि एक गेंदबाजी इकाई के तौर पर हमने लगातार दबाव बनाये रखने के बारे में बात की थी। हम उसे बेहतर तरीके से कर सकते थे। यह ऐसी चीज है जिसे हम इस दौरे के बाकी मैचों में कर सकते है।

आईपीएल के लिए अपने खिलाड़ियों को एनओसी देगा न्यूजीलैंड

मुम्बई। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र के लिए खिलाड़ियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया जाएगा। जिससे ये खिलाड़ी आईपीएल के पूरे सत्र में भाग ले सकें। एनओसी के साथ ही ये भी पक्का किया गया है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईपीएल 2021 के पूरे सत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे। रिचर्ड बूक ने कहा, बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी देगा और कीवी खिलाड़ी आईपीएल के पूरे संस्करण के लिए उपलब्ध होंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के कारण कीवी खिलाड़ी प्लेऑफ मुकाबले नहीं खेल पाएंगे पर न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रवक्ता के बयान से इन अफवाहों पर विराम लग गया है। आईपीएल के इस साल 2021 अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।

मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में सर्व करती हुई चीनी ताइपे की हशीश सू वेई।

37 साल के हुए डि विलियर्स

जोहांसबर्ग, (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान एबी डि विलियर्स गुरुवार को 37 साल के हो गये। डि विलियर्स को अपनी शानदार खेल के लिए सुपरमैन तक कहा जाता है। साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विलियर्स दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान और आक्रामण बल्लेबाज रहे हैं। इसके अलावा वह आईपीएल सहित विश्व की कई क्रिकेट लीग से भी जुड़े हैं। विलियर्स आईपीएल में आरसीबी से खेलते हैं। उन्होंने साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

डि विलियर्स ने जूनियर लेवल पर गोल्फ, टेनिस और रग्बी भी खेला है पर क्रिकेट से उन्हें लोकप्रियता मिली। केवल 21 साल की उम्र में ही डि विलियर्स को भविष्य का सितारा कहा जाने लगा। एबी ने करियर में दो दोहरे शतक भी लगाये। इसमें से एक पाकिस्तान के खिलाफ और दूसरा भारत के खिलाफ था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नवंबर 2010 में नाबाद 278 रन बनाए यह किसी भी दक्षिणअफ्रीकी क्रिकेटर का टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले अप्रैल 2008 में उन्होंने अहमदाबाद में भारतीय टीम के खिलाफ नाबाद 217 रन बनाए थे।

डि विलियर्स के नाम एकदिवसीय में सबसे तेज शतक लगाने का रेकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने केवल 31 गेंदों पर शतक लगाने के साथ ही 149 रन बनाए थे। उनके नाम एकदिवसीय में 16 गेंदों में अर्धशतक का रेकॉर्ड भी है। वह तीन बार आईसीसी के एकदिवसीय प्लेयर ऑफ द इयर अवॉर्ड विजेता रहे हैं। एबी ने करियर में 114 टेस्ट, 228 एकदिवसीय और 78 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 22 शतक और 46 अर्धशतकों की मदद से कुल 8765 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 278 रन है जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में ठोका था। एकदिवसीय में उन्होंने कुल 9577 रन बनाए जिसमें 25 शतक और 53 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं, टी20 अंतरराष्ट्रीय में 10 अर्धशतकों की मदद से कुल 1672 रन बनाए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट भी लिए हैं।

जोकोविच, सेरेना और ओसाका ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंचे

मेलबर्न, (एजेंसी)। विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच, अमेरिकी की सेरेना विलियम्स और जापान की नाओमी ओसाका ओपन अमेरिकी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गये हैं। पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने यहां अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अंतिम चार में जगह बनायी। सर्बियाई खिलाड़ी ने पहले सेट में पिछड़ने के बाद अच्छी वापसी करते हुए पांचवीं वरीयता प्राप्त जर्मनी के ज्वेरेव को 6-7, 6-2, 6-4, 7-6 से हराया। अब सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना रूस के असलान कारात्सेव से होगा। पहली बार कोई ग्रैंडस्लैम खेल रहे कारात्सेव ने ग्रिगोर दिमित्रोव को 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 से हराकर सनसनी फैला दी। कारात्सेव पेशेवर युग में अपने पहले ही प्रयास में किसी ग्रैंडस्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर महिला एकल में अनुभवी खिलाड़ी सेरेना ने क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप को 6-3, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की।

यहा सेरेना का मुकाबला ओसाका से होगा। हालेप पहले सेट में सेरेना के सामने टिक नहीं पायीं जबकि दूसरे सेट में वह वह 3-1 से आगे चल रही थी पर इसके बाद सेरेना ने लगातार पांच अंक लेकर मैच पर कब्जा कर लिया। वहीं महिला एकल के ही एक अन्य मुकाबले में ओसाका ने सीधे सेटों में जीत के साथ ही सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ओसाका ने 35 वर्षीय सीह सु वेई को 6-2, 6-2 से हराया। अब अगले दौरा में जापान की इस महिला स्टार खिलाड़ी का मुकाबला सेरेना से होगा।

कोहली की कप्तानी में 83 फीसदी टेस्ट के रिजल्ट निकले

नई दिल्ली, (संवाददाता)। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रन से हराया। विराट कोहली की कप्तानी में यह हमारी 34वीं जीत है, 14 में हार मिली है। उन्होंने अब तक 58 मैच में कप्तानी की है। यानी वे उनकी कप्तानी में 83 फीसदी टेस्ट में रिजल्ट आते हैं। यह बतौर भारतीय कप्तान सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। कोहली दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले टॉप-5 कप्तान की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इन पांच कप्तान के रिजल्ट के प्रतिशत की बात की जाए तो कोहली ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ के नजदीक हैं। यानी कोहली के कप्तानी करने की स्टाइल इन दिग्गजों से मिलती है। वैसे भी कोहली आक्रामक कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी हैं, विराट कोहली देश में सबसे सफल कप्तान हैं। उन्हें 2014 में कप्तानी दी गई थी। कोहली ने अब तक 7 देशों के खिलाफ कप्तानी की है। सबसे ज्यादा 12 मैच में कप्तानी इंग्लैंड के ही खिलाफ की है। इनेमें से 6 मैच में जीत मिली है जबकि 5 में हार। एक मुकाबला ड्रॉ रहा। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 10-10 मैच में कप्तानी की।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच जीते जबकि 4 में हार मिली है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 मैच में जीत मिली और सिर्फ दो मुकाबले हारे हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 में से 3 जीते, 2 हारे और श्रीलंका के खिलाफ 9 में से 6 जीते, 1 हारे। कोहली ने बांग्लादेश और विंडीज के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। विंडीज के खिलाफ 8 में से 6 जबकि बांग्लादेश के खिलाफ 4 में से 3 मैच जीते हैं। स्टीव वॉ के टेस्ट कप्तानी के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 57 मैच में कप्तानी की। 41 में जीत मिली जबकि 9 हारे। यानी उनकी कप्तानी के दौरान 88 फीसदी मैच के रिजल्ट निकले। वहीं रिकी पोंटिंग को देखें तो उन्होंने 77 मैच में कप्तानी की। 48 जीते, 16 हारे। यानी उनकी कप्तानी में लगभग 83 फीसदी मैच के रिजल्ट आए। लेकिन अपनी कप्तानी में बतौर बल्लेबाज कोहली का रिकॉर्ड पोंटिंग और वॉ से अच्छा है। कोहली ने अपनी कप्तानी में 60 की औसत से लगभग 5365 रन बनाए हैं। इसमें 20 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। पोंटिंग की बात की जाए तो उन्होंने 52 की औसत से 6542 रन बनाए। 19 शतक लगाए। यानी पोंटिंग औसत और शतक दोनों मामलों में कोहली से पीछे हैं। वॉ ने 52 की औसत से 3714 रन बनाए। 15 शतक लगाए। टेस्ट में सबसे सफल कप्तान की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ टॉप पर हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 53 मैच जीते हैं। रिकी पोंटिंग ने 48, स्टीव वॉ ने 41, विंडीज के क्लाइव लॉयड ने 36 और कोहली ने 34 मैच जीते हैं।

डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया

जोहांसबर्ग, (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। डुप्लेसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह खेल को अलविदा कह रहे हैं और यह उसके लिए सही समय है। डुप्लेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर लिखा कि मेरा दिल इस फैसले को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। यह नई शुरूआत करने के लिए बिल्कुल सही समय है। डुप्लेसी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 69 टेस्ट में 40 से कुछ ज्यादा की औसत से 4163 रन बनाए थे। उन्होंने इस प्रारुप में कुल 10 शतक और 21 अर्धशतक लगाए थे। डुप्लेसी ने कोरोना महामारी को लेकर लिखा, यह हम सभी के लिए कठिनाई से लड़कर आगे बढ़ने वाला साल रहा। कभी अनिश्चितता भी रही, पर इससे कई पहलुओं को लेकर मेरी स्पष्ट राय बनी। मेरा दिल

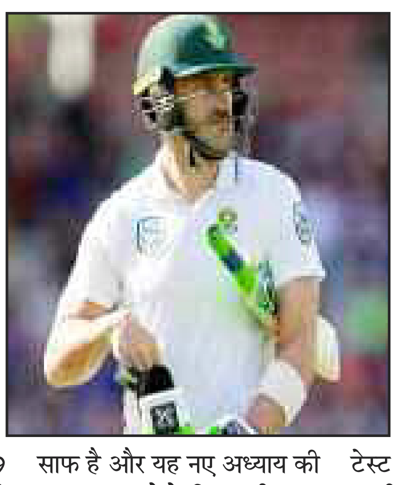

साफ है और यह नए अध्याय की शुरूआत करने के लिए सही समय है।

उन्होंने कहा, खेल के सभी प्रारूपों में देश का प्रतिनिधित्व करना सम्मान है, पर अब मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का समय आ गया है। डुप्लेसी ने कहा, अगले दो साल आईसीसी टी20 विश्व कप होगा। इस वजह से मैं अपना ध्यान इस प्रारूप पर केंद्रित कर रहा हूं। उन्होंने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट और टी20 कप्तान का पद छोड़ दिया है। उन्होंने साल 2016 में एबी डिविलियर्स से यह जिम्मा संभाला था। डुप्लेसी ने हाल में ही पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज खेले थे पर अधिक रन नहीं बना पाये। उन्होंने पहले टेस्ट में 33 और दूसरे में 22 रन बनाए थे। दोनों ही टेस्ट में मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इसके बाद से ही उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठ उठने लगे थे। हालांकि, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दो महीने पहले हुई घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी। सेंचुरियन में हुए पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 199 रन बनाए थे। यह उनके टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर भी था।

सहवाग ने इंग्लैंड की टीम को किया ट्रोल, मोटेरा की पिच की गारंटी नहीं!

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच को लेकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ट्रोल करते हुए कहा कि मोटेरा की पिच की भी गारंटी नहीं है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ही दोनो टीमों के बीच दिन-रात्रि का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। सहवाग ने मेहमान टीम के साथ ही पिच की आलोचना करने वाले पूर्व कप्तान माइकल वान पर भी निशाना साधा है। सहवाग ने ट्विटर पर मीम शेयर कर इंग्लैंड टीम पर निशाना साधा। सहवाग ने हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का एक फोटो शेयर किया। इस तस्वीर के जरिए वीरू ने मेहमान टीम और वॉन को ट्रोल कर दिया। वान चेन्नई की पिच को लेकर नाराज थे। वॉन ने चेन्नै की पिच को बीच यानी समुद्र का किनारा कहा था। वहीं दूसरी और भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने इसी पिच पर शतक लगाकर दिखाया कि पिच पर रन भी बनाये जा सकते हैं।

पहली बार आयरलैंड दौरे पर जाएगी दक्षिण अफ्रीकी टीम

जोहानिसबर्ग, (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीकी टीम जुलाई में सीमित ओवरों के पहले पूर्ण दौरे के लिए आयरलैंड जायेगी। आयरलैंड बोर्ड के अनुसार यह मैच 11 से 25 जुलाई के बीच खेले जाएंगे। इनमें तीन एकदिवसीय और तीन टी20 मैच होंगे। मैच मालाहाइड और स्टोरमोंट में खेले जाएंगे। वहीं क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने अपने एक बयान में कहा कि पहली बार दक्षिण अफ्रीका की टीम एक से अधिक मैच खेलने के लिए आयरलैंड जाएगी।

आईपीएल में दर्शकों के प्रवेश पर अभी फैसला नहीं लिया : गांगुली

कोलकाता, (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में होने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच से दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश मिल सकेगा। एक साल बाद दर्शकों को स्टेडियम में देखकर हमें खुशी होगी। गांगुली ने साथ ही कहा कि यह क्रिकेट के लिए अच्छा संकेत है हालांकि अप्रैल में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सत्र में दर्शकों की वापसी होगी या नहीं, इसे लेकर अभी फैसला नहीं किया गया है। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इसके लिए अंतिम सूची में शामिल 292 खिलाड़ियों में से 61 का चयन होगा। गांगुली ने इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए गुलाबी गेंद से टेस्ट आयोजन को एक अच्छा प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि सीरीज में एक दिन-रात्रि मैच होना अच्छी बात है। इससे टेस्ट क्रिकेट को लेकर रुचि बरकरार रहेगी। उन्होंने

साथ ही कहा कि हर पीढ़ी बदलाव के दौर से गुजरती है। टेस्ट क्रिकेट के लिए गुलाबी गेंद यही बदलाव है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट को बनाये रखने के लिए ऐसी कोशिशें होना जरूरी है. भारत और इंग्लैंड के बीच भी चार टेस्ट की सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नए बने मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा। इस डे-नाइट टेस्ट में प्रशंसकों को स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। यह भारत में गुलाबी गेंद से होने वाला दूसरा टेस्ट होगा। इससे पहले साल 2019 में कोलकाता में दिन-रात्रि टेस्ट हुआ है।

एशिया में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले इंग्लिश कप्तान रुट

नई दिल्ली, (संवाददाता)। जो रूट की कप्तानी में इंग्लिश टीम को दूसरे टेस्ट में 317 रन से हार मिली है। यह बतौर कप्तान रूट की एशिया में पहली हार है। इसके पहले सभी छह टेस्ट में रूट को जीत मिली थी। इसके बाद भी रूट एशिया में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले इंग्लिश कप्तान हैं। एलेस्टेयर कुक 5 जीत के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अन्य कोई इंग्लिश कप्तान एशिया में 5 या उससे अधिक टेस्ट नहीं जीत सका है। जीत के साथ चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। हालांकि, अभी भी दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बनी हुई हैं। तीसरा टेस्ट 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की ओर से 24 कप्तान एशिया में कमान संभाल चुके हैं। इनमें से 11 ने 5 या उससे अधिक मैच में कप्तानी की है। लेकिन दो ही 5 मैच जीत सके हैं। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा 16 मैच में कप्तानी एलेस्टेयर कुक ने की है। 5 में जीत मिली जबकि 8 में हार मिली।माइकल वॉन 10 मैच में कप्तानी के साथ दूसरे नंबर पर हैं। हालांकि वे सिर्फ 2 मैच जीत सके, 3 हारे है। 10 कप्तान जीत ही हासिल नहीं कर सके। सबसे ज्यादा 8 हार कुक की ही कप्तानी में मिली।

इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 134, जबकि दूसरी पारी में 164 रन बनाए थे। दोनों पारियों को मिलाकर 298 रन बने। यानी टीम 300 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। इसके पहले जुलाई 1995 में टीम विंडीज के खिलाफ बर्मिंघम में दोनों पारियों में मिलाकर 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सकी थी। तब टीम ने एक पारी में 147 जबकि एक पारी में 89 रन बनाए थे। तब से टीम ने 317 टेस्ट खेल चुकी हैं। यानी 316 टेस्ट के बाद टीम दोनों पारियों में मिलाकर 300 रन नहीं बना सकी। बतौर इंग्लिश कप्तान एशिया में रन की बनाने की बात करें तो सिर्फ एक ने 1000 से अधिक रन बनाए हैं। अन्य 23 कप्तान ऐसा नहीं कर सके हैं। एलेस्टेयर कुक 1812 रन के साथ टॉप पर हैं। इसमें 7 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। रूट 952 रन के साथ दूसरे पर हैं। इसमें 4 शतक शामिल हैं। वे भारत में पहली बार किसी टेस्ट में 50 से अधिक रन की पारी नहीं खेल सके। सीरीज के दो मैच अभी बचे हैं। इसके बाद रूट 1000 रन तक पहुंच सकते हैं।

नगालैंड के 16 वर्ष के लेग स्पिनर केनसे पर रहेंगी नजरें

कोलकाता, (एजेंसी)। आईपीएल के 14 वें सत्र के लिए गुरुवार को होने वाली नीलामी में नगालैंड के 16 वर्ष के लेग स्पिनर खरीवित्सो केनसे पर सबकी नजरे रहेंगी। केनसे के बारे मे खास बात यह है कि इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वार्न की वीडियो देखकर ही स्पिन गेंदबाजी सीखी है। नीलामी में उसकी बेस प्राइज 20 लाख रुपए है और अटकलें हैं कि मुंबई इंडियंस तथा राजस्थान रॉयल्स दोनों ही उसे खरीदना चाहते हैं। केनसे नीलामी में शामिल 292 खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र के हैं। इस गेंदबाज ने कहा कि पहले मैं ऑफ स्पिन डालता था पर मेरी ऊंगलियों में दर्द हो जाता था। फिर मैने लेग स्पिन डालना शुरू किया। मेरे पास कोई कोच नहीं था तो मैने टीवी और फोन पर वॉर्न के वीडियो देखने शुरू किए। उन्होंने कहा कि वह जिस तरह से गेंद को टर्न कराते हैं, वह मुझे बहुत पसंद है। मैंने लेग स्पिन अपने आप सीखी है। एक कोच अंडर 16 क्रिकेट में मेरा मार्गदर्शन करते थे।

फिंच, राय सहित इन खिलाड़ियों को मिल सकती है मोटी राशि

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आईपीएल 2021 के 14 वें सत्र लिए गुरुवार को होने वाली नीलामी में एविन लुईस और जेसन राय सहित इन 11 विदेशी खिलाड़ियों को मोटी राशि मिल सकती है। संचालन परिषद ने निलामी के लिए खिलाड़ियों की संख्या में कटौती की है जिसके बाद 292 खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे। इस दौरान आठ फ्रेंचाइजी 61 स्थानों को के लिए बोली लगाएंगे। नीलामी की सूची में 164 भारतीय, 125 विदेशी और एसोसिएट देशों के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है।

एरॉन फिंचः सीमित ओवर क्रिकेट में एरॉन फिंच सबसे अहम खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 66 टी-20 मैचों में फिंच ने 2149 रन बनाये हैं। उनका औसत 37.7 और स्ट्राइक रेट 154.05 है। फिंच ने दो शतक और 12 अर्द्धशतक लगाये हैं।

इविन लुईसः वेस्टइंडीज के ओपनर इविन लुईस विस्फोटक बल्लेबाज हैं। उन्होंने 158 टी-20 में 4452 रन, 30.7 की औसत और 142.28 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। इनमें 4 शतक और 30 अर्द्धशतक हैं। उनका स्ट्राइक रेट 155.4 है।

जेसन रायः इंग्लैंड के ओपनर जेसन राय किसी भी आईपीएल टीम के लिए विस्फोटक ओपनर साबित हो सकते हैं। टी20 में उनकी स्ट्राइक रेट 144 और वनडे में 107 है। जानी बेयरेस्टो के साथ वह दुनिया की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी बनाते हैं।

स्टीव स्मिथः ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पिछले कुछ सालों में टी20 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। स्मिथ ने 209 टी20 मैचों में 30.6 की औसत से 4000 रन बनाए हैं। वह मध्यक्रम के वह अच्छे बल्लेबाज हैं।

डेविड मलानः इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान ने करियर की शुरूआत में 19 मैचों में 53.43 की औसत से 855रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 9 अर्द्धशतक बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 149.47 है।

ग्लेन मैक्सवेलः ग्लेन मैक्सवेल को नीलामी में देखना शानदार होगा। आईपीएल 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए वह 13 मैचों में केवल 109 रन बना पाए। उनका औसत 15.42 और स्ट्राइक रेट 101.88 रहा। बावजूद इसके वह सीमित ओवर क्रिकेट के आक्रामक बल्लेबाज हैं। वन डे में उनका स्ट्राइक रेट 125.43 और टी20 में 157.95 है।

क्रिस मौरिसः दक्षिण अफ्रीका के ऑल राउंडर क्रिस मौरिस टी20 के शानदार ऑल राउंडर है। यूएई में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। मौरिस की स्ट्राइक रेट टी20 में 151.02 है. वह 218 मैचों में 17 की औसत और 7.75 की इकोनॉमी से 270 विकेट लिए हैं।

एलेक्स कैरीः ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी राष्ट्रीय टीम में अच्छा प्रदर्शन कर किया है। एकदिवयीय में उन्होंने टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन टी20 में वह यही प्रदर्शन दोहरा नहीं सके।

आदिल राशिदः इंग्लैंड के इस लेग स्पिनर ने 179 टी20 में 201 विकेट लिए है। उनका औसत 22.58 और स्ट्राइक रेट 18.2 है. किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए आदिल राशिद बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

झाय रिचर्डसनः ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन काफी शानदार खिलाड़ी हैं. 2021 की बिग बैश लीग में उन्होंने पर्थ स्क्रॉचर्स के लिए सर्वाधिक 29 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट 7.69 था।